अवध की आवाज

www.avadhkaawaz.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रकाशित

वर्ष–12 अंक–212 R.N.I.- UPHIN/2012/45127 लखनऊ शुक्रवार 1 दिसम्बर 2023 पृष्ठ – 4 मूल्य–3 रूपया

कुछ लोग विकास के एजेंडे को पीछे धकेलना चाहते हैं : योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी खास राजनीतिक दल का नाम लिये बगैर कहा कि कुछ लोग परिवारवाद, जातिवाद, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने का कुत्सित प्रयास कर विकास के एजेंडे को पीछे धकेलना चाहते हैं। श्री योगी ने भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुये गुरुवार को कहा कि कुछ लोग देश का विकास नहीं चाहते हैं। वह परिवारवाद, जातिवाद, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने का कुत्सित प्रयास कर विकास के एजेंडे को पीछे धकेलना चाहते हैं। इससे हम सभी को बाहर आना होगा तभी गरीब के चेहरे पर उसके सपनों की खुशहाली लाई जा सकेगी। उन्होने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साढ़े नौ वर्षों में अपने महत्वपूर्ण निर्णयों, दूरदर्शी सोच एवं योजनाओं से देश भर में जो माहौल बनाया है, वह किसी भारतीय से छिपा नहीं है। इस संकल्प में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं काफी सहायक बनी हैं, जिसका भव्य रूप आज हम सभी को देखने को मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आने वाले कुछ वर्षों में विकसित भारत की संकल्पना को स्थापित करेगी। इसमें हम सब का भी योगदान जरूरी है। इसी उद्देश्य से 15 नवंबर को

जनजातीय गौरव दिवस पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश 1947 में आजाद हुआ था। उसके बाद कई सरकारें बनीं। इन्होंने काम भी किया होगा और देश का पैसा भी खर्च किया होगा, लेकिन दुनिया में वर्ष 2014 से पहले भारत की छवि एवं यहां के लोगों के बारे में क्या धारणा थी, लेकिन दुनिया में आज क्या छवि है, यह हम सब देख रहे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को दर्शाता है। वर्ष 2014 से पहले देश में चेहरा देखकर योजनाएं बनाई जाती थीं। उसमें भी जमकर बंदरबांट का खेल होता था। उनके एजेंडे में गरीब, सामान्य नागरिक, महिलाएं और नौजवान शामिल नहीं होते थे। आज देश में गरीबों और जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, गरीबों के घर में निशुल्क शौचालय, जनधन अकाउंट योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम सम्मान निधि और पीएम स्वनिधि जैसी तमाम लोककल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होने कहा कि यह योजनाएं पहले क्यों नहीं चलायी गई, जबकि देश भी वही है और सरकार के आय के स्त्रोत भी वही हैं। सरकार आपके बारे में सोच रही है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग दें। केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। इसी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण मिशन से जुड़ी सभी योजनाओं की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह को सौंपी गई, जिसका लाभ 60 हजार महिलाएं सीधे–सीधे रोजगार के जरिये उठा रही हैं। वहीं बैंकिंग सुविधा का लाभ ग्रामीणों को देने के लिए बीसी सखी बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा, महापौर सुषमा खर्कवाल, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, विधायक योगेश शुक्ला, डॉ. नीरज बोरा आदि उपस्थित रहे।

लोकसभा चुनाव में होगा बहुकोणीय संघर्ष, बसपा की भूमिका होगी अहम : मायावती

लखनऊ, (यूएनएस)। आगामी लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने के लिये कैडरों को तैयार रहने का आवाहन करते हुये बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने कहा कि केन्द्र व उत्तर प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों एवं कार्यप्रणाली के कारण आम चुनाव में बहुकोणीय संघर्ष होने के पूरे आसार हैं जिसमें बसपा की भूमिका अहम होने वाली है। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में पार्टी की तैयारियों की समीक्षा बैठक में सुश्री मायावती ने गुरुवार को कहा कि देश और यूपी समेत विभिन्न राज्य सरकारों की संकीर्ण, जातिवादी तथा जनविरोधी नीतियों एवं कार्यप्रणाली के कारण राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं तथा ऐसे में किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं होकर बहुकोणीय संघर्ष का रास्ता लोग चुनने को आतुर नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोकसभा का अगला आमचुनाव दिलचस्प, संघर्षपूर्ण और व्यापक जनहित एवं देशहित में साबित होने की प्रबल संभावना है, जिसमें बसपा की भूमिका अहम होगी। उन्होने कहा कि ऐसे हालात में पार्टी को समय–समय पर दिये जा रहे दिशा–निर्देशों पर ईमानदारी व निष्ठापूर्वक मेहनत करके अच्छा रिजल्ट हासिल किया जा सकता है। ऐसा होने पर बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के 'आत्म सम्मान व स्वाभिमानी मूवमेन्ट' को न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में मजबूती मिलेगी तथा समस्त गरीबों, वंचितों, शोषितों–पीड़ितों में से खासकर सदियों से जातिवाद के शिकार दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्गों के साथ–साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों में से विशेषकर मुस्लिम समाज के करोड़ों लोगों को जुल्म–ज्यादती, द्वेष, भेदभाव व दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह के सरकारी व्यवहार से मुक्ति मिल जाएगी। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि इसके लिए विरोधी पार्टियों और उनकी सरकारों के साम, दाम, दण्ड, भेद आदि सभी किस्म के हथकण्डों को अपनी बहुजन एकता और एकजुटता तथा सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने की अपनी चाहत ललक को ठोस लोकतांत्रिक मजबूती प्रदान करना जरूरी होगा, जो 'बहुजन समाज' के लिए मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ऐसा उन्होंने खासकर यूपी में अनेको बार करके देश को दिखाया है। सम्बोधन से पहले मायावती ने पार्टी की पिछली बैठक में दिये गये जरूरी दिशा–निर्देशों पर जमीनी स्तर पर होने वाले अमल की जिला व मण्डलवार समीक्षा रिपोर्ट लेने के

बाद उन्हें अमलीजामा पहनाने में आने वाली कमियों को दूर करके आगे बढ़ने के लिये नये दिशा–निर्देश दिये। उन्होने कहा कि पाँच राज्यों में विधानसभा आमचुनाव के बाद अब लोकसभा के लिये फिर से यहाँ माहौल काफी गरमाने लगा है तथा नई सरगर्मी भी शुरू हो गयी है। सुश्री मायावती ने कहा कि इस बार इस कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया है जिसके तहत् अब पश्चिमी यूपी के छह मण्डलों तथा आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ तथा सहारनपुर मण्डल के लोग नोएडा में बसपा की सरकार द्वारा दिल्ली–यूपी सीमा पर निर्मित भव्य 'राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल व ग्रीन गार्डेन' में पूरी सामूहिकता के साथ अपने मसीहा बाबा साहेब डा. अम्बेडकर को अति–प्रभावी तौर पर श्रद्धा–सुमन अर्पित करेंगे, जबकि यूपी के शेष 12 मण्डलों में पार्टी के लोग 'डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल' प्रांगण में स्थित डा. अम्बेडकर स्मारक में अपने मसीहा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उन्होने कहा कि रोजी–रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, सुख–शान्ति, समृद्धि के 'अच्छे दिन' को तरसते उत्तर प्रदेश के लगभग 25 करोड़ लोगों के जीवन में छाई गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन व पलायन के दुःख भरे जीवन की बात है। यह भाजपा के शासनकाल में भी लगातार जारी है, बल्कि वास्तविकता यह है कि पिछले वर्षों में लोगों का दुःख–दर्द घटने के बजाय सरकारी वादों, दावों व घोषणाओं के विपरीत हालात और बिगड़े हैं तथा लोगों का जीवन त्रस्त हुआ है। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की सरकार में भी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में समग्र विकास के बजाय इनमें से मात्र कुछ गिने–चुने जिले को ही उसी प्रकार से सरकारी धन व्यय को प्राथमिकता दी जा रही है जिस प्रकार से सपा के शासनकाल में कुछ चुनिन्दा जिले ही सरकारी कृपादृष्टि के पात्र हुआ करते थे और जिस संकीर्ण राजनीति से जनता पहले की तरह ही दुःखी व त्रस्त है। उन्होने कहा कि साफ है कि भाजपा भी, सपा व कांग्रेस की तरह अपने काम के बल पर जनता से वोट माँगने की स्थिति में नहीं है और इसीलिए उसे घोर चुनावी स्वार्थ की राजनीति के लिए संकीर्ण, भड़काऊ एवं विभाजनकारी मुद्दों का फिर सहारा लेने की जरूरत है, जिससे बहुजन समाज के लोगों को बहुत सावधान रहना है।

संक्षिप्त समाचार

शराब की दुकानों पर चले तो स्वामी ओमवेश योगी के बुलडोजर का ड्राइवर बनने को तैयार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज बिजनौर की चांदपुर सीट से सपा विधायक स्वामी ओमवेश ने शराब बंदी की मांग करते हुए कहा कि वह योगी के बुलडोजर का ड्राइवर बनने को तैयार हैं। बस सरकार अपने बुलडोजर शराब की दुकानों पर चला दे। इसपर सदन सत्ता पक्ष के विधायक मुस्कुराने लगे। स्वामी ओमवेश ने सदन में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा–महाना जी आप महान हैं। महाना बोले कि मुझे मक्खन लगाने से फायदा नहीं है। स्वामी ओमवेश ने कहा कि कुछ दिन पहले मुझे डेंगू बुखार हुआ था। मेरे पास सीएम योगी आदित्यनाथ ने हालचाल जानने के लिए फोन किया। उन्होंने कहा कि आपके इतने विशालकाय शरीर में मच्छर का असर कैसे हो गया। अगले दिन ही मेरा बुखार उतर गया। स्वामी ओमवेश ने सरकार से कहा कि शराब खरीदने से पहले आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य किया जाए। इस पर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि इसमें आधार अनिवार्य नहीं हो सकता।

यूपी में नौकरशाहों के खिलाफ जांच के लिए बने व्यवस्था : भाजपा

लखनऊ। अफसरों के खिलाफ आरोपों की जांच एक निर्धारित समय सीमा में हो। इसकी मांग अब विधायिका से उठने लगी है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भाजपा के एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने मांग की है कि 110 सूचना के तहत सांसद–विधायक की तरह नौकरशाही पर चल रहे भ्रष्टाचार के केसों के लिए एक व्यवस्था बने, जिससे इन पर लगे आरोपों की जांच हो सके। गुरुवार को सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए एमएलसी ने चर्चा की मांग की। भाजपा के एमएलसी ने कहा कि सांसद या विधायक पर होने वाले मुकदमों की सुनवाई के लिए एमपी एमएलए कोर्ट हैं। मगर अफसरों के खिलाफ होने वाली शिकायतों की जांच और उन पर कार्रवाई के लिए कोई व्यस्था नहीं है। कई बार तो अफसरों के खिलाफ होने वाली जांच में इतनी देर हो जाती है कि अफसर रिटायर हो जाते हैं। मगर उनके खिलाफ कोई करवाई नहीं हो पाती है। इस बारे में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवानिवृत्त योगेंद्र नारायण का कहना है कि जिस प्रकार से सांसद और विधायक के लिए भ्रष्ट्राचार और अपराध के मामले सुनने के लिए एमपी एमएलए कोर्ट बनी है। ऐसी नौकरशाह के लिए भी कोर्ट जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि नौकरशाह सरकार को प्रस्तुत करते हैं। इनके ऊपर चल रहे कदाचार के मामले पर शीघ्र सुनवाई की व्यवस्था होनी चहिए।

पुरानी पेंशन बहाली के लिए हड़ताल को सहमत हुए कर्मचारी शिक्षक

लखनऊ। पुरानी पेंशन बहाली के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर किए जा रहे आन्दोलन के क्रम में अब कार्मिको और शिक्षकों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। इस संदर्भ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की केन्द्रीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार हर विभाग के कार्मिकों और शिक्षकों से आन लाइन और ऑफलाइन सहमति पत्र मांगे गए थे। प्रदेश में यह अभियान 21नवम्बर से तीस नवम्बर तक चलाया गया है। इस अभियान में अब तक 100 प्रतिशत ऑफ लाइन एवं 96.03 प्रतिशत ऑन लाइन सहमति पत्र प्राप्त हुए। यह जानकारी आज संयुक्त परिषद कार्यालय राजभवन के समक्ष जिलाध्यक्ष अमिता त्रिपाठी और जिला मंत्री सुभाष चन्द्र तिवारी ने संयुक्त रूप से दी।पत्रकारों से बॉतचीत में अन्य विभागों के पदाधिकारियों ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार के साझा मंच द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके है। प्रदेश स्तर पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए जनपदों में प्रदर्शन, रथ यात्रा और मौन वृत जैसे आन्दोलन के उपरान्त हड़ताल पर जाने के लिए 21 से 30 नवम्बर तक हड़ताल पर जाने के लिए ब्लाक स्तर से लेकर प्रान्त स्तर तक जनमत संग्रह कराया जा चुका है।पुरानी पेंशन बहाली के लिएपूर्व में लगभग 2 करोड़ नागरिकों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया को पुरानी पेंशन बहाली हेतु पिटीशिन भेजी जा चुकी है। विगत् 21 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली में सम्पन्न राष्ट्रीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से निधारित किये गये कार्यक्रम के अनुपालन में पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर निरन्तर जनसम्पर्क, मशाल जुलूस, पेंशन–रथ यात्रा आदि के कार्यक्रम प्रदेश के कार्मिकों एवं शिक्षकों द्वारा किये जा चुके है। उन्होंने बताया कि अब इन सहमति पत्रों को सांझा मंच के समक्ष रखकर हडताल की तारीख तय की जाएगी। जिसमें राज्य सरकार के कार्मिक, शिक्षक और केन्द्र सरकार के सभी विभाग रेलवे, आयकर, पोस्टल आदि एक साथ मिलकर हड़ताल में उतरेगें। इस दौरान लोक निर्माण विभाग से राजर्षि त्रिपाठी, इं. मस्तराम वर्मा,इं. सुधीर गुप्ता,रामसुरेश, विनोद कुमार, शिक्षक संघ से विनीत सिंह,कृषि विभाग से फहीम अख्तर, समाज कल्याण से धर्मेन्द्र सिंह, सिंचाई से अमरजीत मिश्रा, उद्यान से अविनाश श्रीवास्तव, प्रमोद मिश्रा, अरूण सिंह, राजेश सिंह, फैजल अहमद, आनंद सिंह, आरटीओ से अखिलेश्वर चतुर्वेदी, दिग्विजय सिंह, अशोक सिंह, विवेक, रवि सिंह, शालिनी मिश्रा, अलोक सिंह, मौजूद रहे।

सदन में अखिलेश यादव ने उठाया किसानों की आय का मुद्दा, कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने पूछा सवाल

लखनऊ, (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को प्रश्नकाल के बाद अनुपूरक बजट पर चर्चा हो रही है। इससे पहले बुधवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 28760 करोड़ का अनुपरक बजट पेश किया। बजट पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने इन्वेस्टर समिट को लेकर सवाल पूछा कि सरकार यह जानकारी दें कि इन्वेस्टर समिट के आयोजन पर कितना खर्च हुआ और कितना निवेश आया और कितना निवेश जमीन पर उतर गया, किस जिले में कितना निवेश हुआ है। सपा विधायक डॉ. संग्राम यादव ने सवाल पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जातीय जनगणना कराए जाने पर सरकार विचार करेगी, यदि नहीं तो क्यों? विधान परिषद में एक दिन पहले इसी मुद्दे पर सपा और भाजपा के बीच बहस हो चुकी है। अनुपूरक सवाल के तौर पर उन्होंने पूछा है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तर्ज पर 75: आरक्षण देने पर सरकार विचार करेगी। इस प्रश्न के जवाब में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि डॉ राम मनोहर लोहिया जाति जोड़ने की बात करते थे। डॉ. भीमराव अंबेडकर भी समता मूलक समाज की स्थापना की बात करते थे। उन्होंने कहा कि जहां तक जातीय जनगणना का सवाल है तो यह केंद्र सरकार का विषय है और संविधान की व्यवस्था को तोड़कर राज्य सरकार अपने स्तर से किसी तरह की जनगणना नहीं कर सकती. समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सरकार के जवाब से नाखुश होकर नारेबाजी शुरू कर दी है। इसके विरोध में समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य वॉकआउट कर गए हैं। वहीं, सत्र की शुरुआत में किसानों की आय का मुद्दा जोरशोर से उठाया गया. समाजवादी पार्टी के विधायक अखिलेश ने किसानों की आय दोगुना करने से संबंधित सवाल पूछा है। इस पर चर्चा करते हुए समाजवादी पार्टी विधायक दल के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में कृषि आय दोगुनी नहीं हुई है। लगातार विभिन्न मदों में किसानों की आय घट रही है। सवाल यह है कि किसान फायदे में है या घाटे में है। उन्होंने अलग–अलग आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जिसके मुताबिक किसानों की आय लगातार उत्तर प्रदेश में घट रही है। इसके अलावा किसानों की फसलों को बेसहारा पशुओं के जरिए होने वाले नुकसान का सवाल भी मनोज पांडेय पूछा। इस सवाल को लेकर सदन में बहस जारी हैय इस मुद्दे को लेकर कृषि मंत्री शाही ने आंकड़े रखे तो सपाइयों ने हंगामा शुरू कर दिया कुछ सपा विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मनोज पांडे के सवालों का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने पिछले साढ़े साल के आंकड़े प्रस्तुत करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बताया है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब उत्तर प्रदेश में किसानों का बुरा हाल था। इसके बाद हम लगातार किसानों की आय में बढ़ोतरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार के समय में गेहूं की कीमत 1450 रुपए प्रति कुंतल थी मोदी और योगी की सरकार आने के बाद 2275 रुपए प्रति कुंटल में गेहूं खरीद कर रहे हैं।

यूपी में बदला मौसम का मिजाजय बूंदाबांदी ने बढ़ाई ठंड, अगले तीन दिनों तक बारिश रहेगी जारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश के बाद अब मौसम का मिजाज बदलने है। ठंड बढ़ने लगी है और सुबह–शाम के समय घने कोहरे की चादर छाई रहती है। आज सुबह से ही कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। बारिश ने ठंड तो बढ़ा दी है, लेकिन अभी तक लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं दिला पाई। लोग अभी भी प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे है। इसी बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आने वाले दो तीन दिनों में कई जिलों में बारिश हो सकती है, जिससे सर्दी और बढ़ जाएगी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई हिस्सों में आज सुबह से ही रुक–रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। सुबह से शुरू हुई बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। कई इलाकों में बादल छाए हुए है और ठंडी हवाएं चल रही है। विभाग की मानें तो अगले दो से तीन दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।

पश्चिमी यूपी में एक दो स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। प्रदेश में वायु प्रदूषण की बात करें तो अभी तक लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। आज यानी गुरुवार को नोएडा सेक्टर–125 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 312, ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क फेज–5 का एक्यूआई 338 रिकॉर्ड किया गया है। यहां हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही। जबकि गाजियाबाद में लोनी का एक्यूआई 363 रहा। इसके अलावा बुलंदशहर का एक्यूआई 287, लखनऊ के लालबाग का एक्यूआई 321 रहा, जो बेहद खतरनाक स्तर पर है। वहीं, मेरठ में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है और लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है।

नवयुग में नवागंतुक छात्राओं का स्वागत समारोह आयोजित

लखनऊ। आज नवयुग कन्या महाविद्यालय के विज्ञान संकाय में बी.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर की नवागंतुक छात्राओं का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्या प्रो. मंजुला उपाध्याय द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलन के साथ किया गया। विज्ञान संकाय की वरिष्ठ प्रवक्ताओं द्वारा पौध भेंट कर प्राचार्या एवम अतिथियों का अभिनंदन किया गया। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम में समूह नृत्य, लघु हास्य नाटक, गायन इत्यादि प्रस्तुत किए गए। तृतीय वर्ष की कैफिया इस्लाम के द्वारा प्रस्तुत स्वरचित शायरी ने कार्यक्रम का समां बांध दिया। नवागंतुक छात्राओं के लिए मिस फ्रेशर्स प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। प्रतिभागियों ने प्रथम चरण में रैम्प वॉक एवम द्वितीय चरण में टैलेंट हंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। विजेताओं का चयन अंतिम चरण में छात्राओं द्वारा दिये गए उत्तर के आधार पर निर्णायक मंडल द्वारा किया गया। निर्णायक मंडल में प्रो. अंबिका बाजपेई (इतिहास विभाग), डा. सीमा पांडे (शारीरिक शिक्षा विभाग) एवं डा.सुखमनी गांधी (वाणिज्य विभाग) उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का सफल संचालन तृतीय वर्ष की गरिमा सिंह व अनुप्रिया यादव द्वारा किया गया। निर्णायक मंडल द्वारा सृष्टि मिश्रा को मिस फ्रेशर्स, मानसी बाजपेई को फर्स्ट रनर अप एवं प्रियांशी तिवारी को सेकंड रनर अप चुना गया। प्राचार्या द्वारा छात्राओं को बधाई एवं आशीर्वचन दिए गए और कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए छात्राओं का उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम में विज्ञान संकाय के सम्मानित शिक्षकगण उपस्थित रहे। सभी छात्राओं ने कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाया एवम सूक्ष्म जलपान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

लोकसभा का टिकट न मिला तो उच्च सदन की पकड़ सकते राह

विधान परिषद के कई सदस्यों का पूरा हो रहा कार्यकाल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगले साल लोकसभा चुनाव के साथ ही दो और सियासी लड़ाइयों के लिए बिसात बिछेगी। मार्च–अप्रैल में लोकसभा चुनाव का धमासान मचेगा, उसी समय राज्यसभा और विधान परिषद की 23 सीटें भी रिक्त होंगी। राज्यसभा की यूपी कोटे की 10 सीटें अप्रैल में और विधान परिषद की 13 सीटें मई में खाली होंगी।संख्या बल के लिहाज से सीटों का बंटवारा भाजपा और सपा के बीच ही होगा। लोकसभा का टिकट न पाने वाले नेताओं के पास राज्यसभा या विधान परिषद जाने का विकल्प रहेगा। लोकसभा चुनाव में भाजपा और सपा के पास अपने रूठे क्षत्रपों को मनाने का मौका होगा। लोकसभा चुनाव के लगभग साथ ही उन्हें राज्यसभा और विधान परिषद के प्रत्याशी चुनने होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे चाहे जो भी हों लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद में सपा के पास अपनी स्थिति पहले से बेहतर करने का अवसर है। 2018 में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में भाजपा 9 सीटें पाने में सफल रही थी,जबकि संख्या के गुणा–गणित में सपा सिर्फ जया बच्चन को ही उच्च सदन में भेज सकी थी। विधान परिषद की खाली होने वाले 13 में 10 सीटें भाजपा और उसके सहयोगी अपना दल एस के पास है।सपा और बसपा के पास 1–1 सीट थी।इस बार स्थिति अलग है।सपा–रालोद गठबंधन के पास 118 विधायक हैं, जिसमें 109 सपा और 9 रालोद के हैं। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के पास विधायकों की संख्या 279 है। इस लिहाज से भाजपा के लिए पिछला प्रदर्शन दोहरा पाना कठिन होगा।राज्यसभा मेंभाजपा के अशोक वाजपेयी, अनिल जैन, कांता कर्दम, अनिल अग्रवाल, सकलदीप राजभर, हरनाथ सिंह यादव, सुधांशु त्रिवेदी, जीवीएल नरसिम्हा राव, विजयपाल तोमर और सपा की जया बच्चन का कार्यकाल खत्म होने वाला है। विधान परिषद में भाजपा के विजय बहादुर पाठक, विद्या सागर सोनकर, यशवंत सिंह, सरोजनी अग्रवाल, अशोक कटारिया, बुक्कल नवाब, अशोक धवन, महेंद्र सिंह, निर्मला पासवान, मोहसिन रजा. अपना दल एस के आशीष पटेल सपा के नरेश उत्तम बसपा के भीमराव आंबेडकर का कार्यालय भी खत्म होगा।

सम्पादकीय

बराबरी का हक और बराबरी का दिखावा

अपने उपन्यास एनिमल फॉर्म में जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है– ऑल एनिमल्स आर इक्वल, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल दैन अदर्स। यानी सभी जानवर समान हैं , लेकिन कुछ जानवर दूसरों की तुलना में अधिक समान हैं। बराबरी के दिखावे पर यह अनुपम उदाहरण सोशल मीडिया साइट एक्स की एक पोस्ट को देखकर याद आया।

इसमें एक नोटिस की तस्वीर शेयर की गई थी। नोटिस में अंग्रेजी में लिखा था– हाउस मेड्स, डिलीवरी ब्वॉयज, एंड वर्कर्स शुड नॉट यूज पैसेंजर्स लिफ्ट. इन केस दे आर कॉट, दे विल बी फाइन्ड रू. 1000. ये किस शहर और किस सोसाइटी में लगा हुआ नोटिस है, ये तो पता नहीं, और ये भी कहना कठिन है कि जिन लोगों के लिए यह गैरकानूनी नोटिस चिपकाया गया है, उनमें से कितनों को इसकी भाषा समझ आई होगी। यह नोटिस अंग्रेजी में है, और देश के कामगार तबके के अधिकतर लोग प्रांतीय भाषाओं और बोलियों को ही जानते हैं। इस नोटिस को जिस किसी ने भी तैयार किया है, उसने किस आधार पर पकड़े जाने पर एक हजार रूपए के जुर्माने की बात लिखी है, यह भी समझ से परे है। क्योंकि लिफ्ट में जाना कोई कानूनन अपराध नहीं है। पकड़े जाने जैसी शब्दावली ऐसे लग रही है, मानो चोरी या कत्ल करते हुए कोई पकड़ा गया है। वैसे इस चेतावनीनुमा नोटिस में जो कुछ भी लिखा है, वो नए भारत का कड़वा सच है। करीब 12–15 पहले खबर पढ़ी थी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का गढ़ बन चुके गुड़गांव की एक बहुमंजिला इमारत में घरेलू सहायकों और कुत्तों के लिए अलग लिफ्ट की व्यवस्था की गई है और वहां रहने वाले बाशिंदों के लिए अलग लिफ्ट है। तब देश में यूपीए सरकार थी और मीडिया उद्योगपतियों का पूरी तरह से गुलाम नहीं बना था, इसलिए ऐसी खबरें अखबारों में छप जाया करती थीं। हालांकि समाज में भेदभाव तब भी मौजूद था, अब भी उतनी ही सघनता से विद्यमान है। फर्क इतना ही है कि अब जैसे ही मौका मिलता है, भेदभाव तरल होकर समाज में खुल कर बहने भी लगता है। एक दशक पहले तक समाज में इंसानियत के लिहाज की मात्रा थोड़ी अधिक थी, आंखों में शर्म थोड़ी बहुत दिख जाती थी। अब वह सब बड़ी तेजी से विलुप्त होता जा रहा है। बिल्कुल आयातित चीतों की तरह। बहरहाल, इस नोटिस को देखकर ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि नगरीय जीवन में अब यह आम चलन हो गया है। लगभग हर बहुमंजिला इमारत में कामगारों के लिए अलग लिफ्ट की व्यवस्था है, जिसे सर्विस लिफ्ट कहा जाता है। कोरोना काल में अलग लिफ्ट के नियम का और कड़ाई से पालन होने लगा, क्योंकि संपन्न तबके के लोग यही मानकर चलते हैं कि सारी गंदगी और बीमारियां झुग्गियों में रहने वाले लोग ही उन तक पहुंचाते हैं। यह तथ्य पता नहीं कितने लोगों को याद है कि देश में कोरोना का प्रवेश हवाई यात्रा करने वालों की बदौलत हुआ है। यह भी सोचने की बात है कि आखिर किन कारणों से झुग्गी–झोपड़ियों या निचली बस्तियों में गंदगी और बीमारी फैलती है। क्यों वहां के लोग अच्छी हवा और पानी से वंचित रहते हैं। कौन उनके हक को मारकर अपनी जेबें और कोठियां भर रहा है। चंद लोगों के विलासितापूर्ण जीवन का भुगतान लाखों लोगों को क्यों करना पड़ रहा है। ऐसे सवाल समाज में अक्सर असुविधा पैदा कर देते हैं, इनके जवाब ढूंढने में खुद का सामना आईने से हो जाता है। इसलिए बेहतर यही होता है कि ऐसे मामलों की तह में जाएं ही नहीं और जैसा चल रहा है, वैसा ही चलने दें। जब देश गुलाम था, तब लोगों को खरीदने–बेचने का चलन था, दास प्रथा चलती थी, निचली जाति या हैसियत के लोगों को धन और सत्ता की शक्ति से संपन्न लोगों की चाकरी करनी पड़ती थी। देश आजाद हो गया, तो संविधान निर्माताओं ने भारत की इस सामाजिक सच्चाई को समझते हुए नियम–कानून बनाए। सबके लिए बराबरी का अधिकार निश्चित किया। हालांकि वे भी जानते थे कि भारत अपनी भेदभाव वाली मानसिकता से इतनी जल्दी नहीं उबर पाएगा, फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और अपनी ओर से नए भारत को जो बेहतरीन तोहफा दे सकते थे, वो संविधान के रूप में दिया। अफसोस ये है कि इस संविधान का पूरा लाभ उन नागरिकों को ही नहीं मिल रहा है, जिन्हें खास तौर पर ध्यान में रखते हुए बराबरी के अधिकार को शामिल किया गया है। चाकरी, गुलामी, दासता, जो कह लें, शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों की बदौलत अब भी समाज में विद्यमान हैं। तीन दिन पहले ही देश की सरकार ने संविधान दिवस मनाया है। मोदी सरकार के आने के बाद से 26 जनवरी के साथ–साथ 26 नवंबर का महत्व भी बढ़ा दिया गया है।इस बार तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिन मन की बात भी की, क्योंकि महीने का आखिरी रविवार था। खैर, 26 नवंबर के ही दिन हमारे रिहायशी इलाके के व्हाट्सऐप ग्रुप पर एक चर्चा छिड़ी, जिसमें इस बात पर कुछ लोगों ने आपत्ति जतलाई कि सोसाइटी परिसर के भीतर मौजूद ब्यूटी पार्लर में घर में काम करने वाली मेड्स यानी सहायिकाओं को क्यों प्रवेश दिया जा रहा है। बाकायदा सवाल उठाया गया कि फेशियल, मेनिक्योर, पेडिक्योर या बाल कटवाने के लिए ये सहायिकाएं उस पार्लर में कैसे जा सकती हैं, और इनके पास इतने पैसे कहां से आते हैं कि ये पार्लर का खर्च उठा सकें। कुछ लोगों ने यह मांग भी उठाई कि पार्लर के मालिक के खिलाफ शिकायत कर इसे बंद करवाना चाहिए। इस सवाल को देखकर मन भीतर तक वितृष्णा से भर उठा कि आखिर सभ्य समाज में रहने वाला इंसान इतनी गिरी हुई सोच कैसे ला सकता है और इतना दुस्साहस कैसे जुटा सकता है कि ऐसे सवाल उठाए। हालांकि ये देखकर संतोष हुआ कि कुछ लोगों ने फौरन ऐसे सवाल का प्रतिवाद किया और पूछा कि हम इन मेड्स से अपना घर साफ करवा सकते हैं, इनका बनाया भोजन ग्रहण कर सकते हैं, अपने बच्चों को इनके भरोसे छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ये अपने सौंदर्य पर अपने पैसे खर्च करना चाहें और संपन्न घरों की महिलाओं की तरह पार्लर में जाएं, तो किसी को तकलीफ क्यों होनी चाहिए। कामगारों के लिए अलग लिफ्ट से होते हुए बात पार्लर जाने पर आपत्ति तक पहुंच गई, लेकिन मूल सवाल वही बना हुआ है कि आखिर धर्म, जाति, नस्ल और आर्थिक स्थिति का यह भेदभाव किस तरह खत्म होगा। संविधान ने केवल रास्ता दिखाया है, उस पर चलने की इच्छाशक्ति समाज को ही दिखानी होगी। फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग काफी चर्चित हुआ था, जिसमें वे एक बिल्डिंग को खरीदते हैं और कहते हैं कि आपने इसके 10 लाख रूपए और मांगे होते तो भी मैं दे देता। आज से बीस बरस पहले जब ये बिल्डिंग बन रही थी, तो मेरी मां ने इसमें ईंटें उठाई थीं। आज मैं ये बिल्डिंग अपनी मां को तोहफे में देने जा रहा हूं। अब जिंदगी तो कोई फिल्म नहीं है, जिसमें इस तरह के संवाद कहने–सुनने मिलें। ऊंची इमारतों से लेकर, चौड़ी सड़कों और उत्तरकाशी के सिलक्यारा में बन रही सुरंग तक, सबमें मजदूरों का खून–पसीना लगा होता है। एक बार निर्माण हो जाने के बाद इन पर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाता है। मजदूर न लाखों–करोड़ों के घरों में कभी रह पाते हैं, न इन सड़कों पर रफ्तार भरने वाली गाड़ियों पर सवार हो पाते हैं। उन्हें उनकी मजदूरी के अतिरिक्त कोई तोहफा भी नहीं मिलने वाला। लेकिन संविधान में उनको जिस बराबरी का हक मिला हुआ है, उसे किसी भी तरह न मारा जाए, इतना ही ध्यान समाज रख ले तो गैरबराबरी दूर करने में यह बड़ा कदम होगा। फिर किसी बेटे को अपनी मां को तोहफा देने के लिए बेईमानी की राह पर नहीं चलना पड़ेगा।

सिलक्यारा सुरंग की घटना से सरकारों को सबक सीखने की जरूरत है

दृढ़ इच्छाशक्ति, लगन, उम्मीद, सकारात्मकता और हौसले की ताकत ने मिलकर आखिर प्रकृति के साथ लड़ी 17 दिन की जंग में जिन्दगी को विजयी बना दिया। सिलक्यारा सुरंग में आठ राज्यों के 41 मजदूरों को सकुशल जिन्दा निकाल लेने के 400 घंटों तक चले संघर्ष में जीत इंसान के चट्टानी हौसले के नाम दर्ज हुई। उत्तरकाशी टनल में फंसे इन सभी मजदूरों को जब मंगलवार रात सुरक्षित निकाला गया, तो देश ने राहत की सांस ली और दीपावली मनाई। यह बचाव अभियान प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय बना है। जिसमें विज्ञान में विश्वास एवं आस्था ने मनोबल दिया। दीपावली के दिन से टनल में फंसे मजदूरों का सुरक्षित बाहर आना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा सकता। बचाव अभियान में हर मोड़ पर आती बाधाओं से बार–बार निराशा एवं नाउम्मीदी के बादल छाए जरूर, लेकिन बचाव दल के अथक प्रयास आखिर में रंग ले ही आए। बजाव कार्य में जुटे जाम्बाज राहत कर्मियों का भरोसा, केन्द्र एवं राज्य सरकार की पूरी ताकत एवं पूरे देश की प्रार्थनाओं का ही असर था जो डर, निराशा और दुश्चिंताओं को दूर करने का हौसला बराबर देता रहा।

17 दिन तक संकटकालीन स्थितियों में मजदूरों को जीवित रखने की चुनौती वाकई बहुत बड़ी थी, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी थीं। मजदूरों तक ऑक्सीजन और भोजन पानी पहुंचाना भी आसान नहीं था। तरह–तरह की बाधाओं एवं तकलीफों के बीच जिन्दगी बचाने की मुहिम निश्चित ही एक रोशनी बनी। इसमें सुरंग में फंसे मजबूरों ने जहां हर तरह से जिजीविषा एवं बहादूरी का परिचय दिया, वहीं बचाव कार्य में जुटे वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, तकनीकी जानकारों एवं कर्मियों ने दिन–रात एक करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया। यह बचाव अभियान एवं इसकी सफलता ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय उदाहरण बनकर प्रस्तुत हुआ है। दुविधा एवं मौत की सुरंग में कैद हुए मजदूरों को संकट से आजादी मिली, लेकिन सिलक्यारा की इस घटना ने अनेक सवाल भी खड़े किए हैं। सवाल यह है कि एक प्लान के विफल होने पर दूसरा और आगे के विफल होने पर ही तीसरा, चौथा, पांचवां प्लान क्यों बना? क्या पांच प्लान पहले ही तैयार नहीं हो सकते थे?

बीते दो दशकों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क–क्रांति ने विकास की नई इबारत लिखी है, चारधाम सड़क परियोजना, पहाड़ी क्षेत्रों एवं दुर्गम्य स्थलों में भी यातायात सुगम करने के लिए पहाड़ खोदकर टनल बनाए जा रहे हैं, जिनमें दुर्घटनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। प्रश्न है कि संभावित दुर्घटनाओं से बचने के आवश्यक उपकरण क्यों नहीं जुटाये गये? मलबा हटाने के लिए अमेरिका से क्यों मशीन मंगवानी पड़ी, भारत में ऐसी मशीनों की उपलब्धता क्यों नहीं है? ऐसी विपत्तियों एवं संकटों से उबरने की हमारी तैयारी आत्म–निर्भर एवं स्वावलम्बी क्यों नहीं बनायी जाती? क्यों नहीं अपने देश में जगह–जगह बढ़ती सुरंग परियोजना को देखते हुए एक ऐसे राष्ट्रीय संस्थान खड़ा किया जाता जो बिना भ्रष्टाचार एवं कोताही में लिप्त हुए निर्माणाधीन परियोजनाओं का हर वर्ष तकनीकी ऑडिट करे, जैसा कि सरकारी संस्थानों में वित्तीय ऑडिट होता है। तब हम ऐसे हादसों को रोक पाएंगे।

हिमालय जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी बड़ी सड़क परियोजनाओं एवं अन्य निर्माण कार्यों की इजाजत देने से पहले उस पर व्यापक मंथन–अनुसंधान–जांच एवं शोध की अपेक्षा है। किस तरह के निर्माण कार्यों की इजाजत दी जाए और किस तरह के काम को नहीं, यह भी समझना एवं एक रोडमैप बनाना होगा। पर्यावरणविद और भूविज्ञानी ऐसे निर्माण कार्यों को पर्यावरण के लिये गंभीर खतरा मानते रहे हैं, ऐसे लोग लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि हिमालय एक कच्चा पहाड़ है, वहां बड़ी परियोजनाओं को अनुमति देने से पहले सब तरह की जांच कर लेनी चाहिए। संभावित खतरों पर संवेदनशीलता से चिन्तन करना चाहिए। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में बन रही सुरंग में भी यह बात सामने आई है कि इस जगह के आसपास दो स्थानीय फॉल्टों की उत्तर से दक्षिण तक कटान है। क्या इस सुरंग को बनाने से पहले इसका अध्ययन नहीं किया गया था? बचाव कार्य के लिए यहां आए विदेशी सुरंग विशेषज्ञों ने शेयर जोन की बात कही। शेयर जोन उसे कहते हैं, जिसके आसपास से दो नदियां एक–दूसरे को क्रॉस करती हैं। भूकंप जोन होने से भी ऐसे इलाकों में भू–धंसान की समस्या आती है। खुदाई करने वाले कई मजदूरों ने भी इस बात को रेखांकित किया एवं चेताया कि सुरंग से बार–बार धसकते मलबे की समस्या है, मगर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रश्न है कि कौन लोग इस उपेक्षा के लिये जिम्मेदार हैं। इसलिए यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर संवेदनशीलता की जरूरत है।

खान या सुरंग में मजदूरों के फंसने की घटनाएं देश ही नहीं दुनियाभर में होती रहती हैं। कभी पहाड़ के धंसने से और कभी खदानों में पानी भरने से भीषण हादसे होते रहते हैं। जहां विकास की गंगा बहती है, वहां विनाश की संभावना से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हमें संभावित खतरों पर अधिक गंभीर होने की अपेक्षा है। मैदानी इलाकों में ही नहीं, उच्च हिमालयी क्षेत्र में भी सड़क, रेल और जलविद्युत परियोजनाओं तक के लिए सुरंगों का जाल बिछाया जा रहा है, क्योंकि सुरंगों को बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है। क्या सुरंगें वाकई बेहतर विकल्प हैं? कैसे हो रहा है उनका निर्माण? इन प्रश्नों पर व्यापक मंथन की अपेक्षा है। ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसी परियोजनाएं हर जगह ऐसी दुर्घटनाओं की शिकार हुई है। कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो की कई जटिल सुरंगों पर सफलतापूर्वक काम हुआ है। उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर एंड प्लानिंग बृजेश मिश्रा के अनुसार, सुरंग परियोजना में सबसे अहम जियो टेक्निकल इंवेस्टिगिशेन होता है, इसी से तय होता है कि सुरंग खुदाई के बाद कितनी देर तक टिक पाएगी। निर्माण के दौरान कोई बड़ा अवरोध या खतरा तो नहीं होगा। साथ ही, इसे किस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत है, पर दुर्गम पहाड़ में कई बार जांच उपकरण अधिक ऊंचाई तक ले जाना मुश्किल हो जाता है और जियो टेक्निकल इंवेस्टिगिशेन पर समग्रता से कार्य नहीं होता। कई बार राजनीतिक कारणों से जल्द काम निपटाने के दबाव में सुरंग के मुहाने पर किए गए अध्ययन के आधार पर ही काम शुरू कर दिया जाता है, जो बाद में बहुत भारी पड़ता है। ऐसे मामलों में बहुत कारगर कथन है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। उत्तराखंड सुरंग हादसे में शायद ऐसा ही हुआ।

सिलक्यारा की घटना से एक तथ्य और सामने आया है कि ऐसे बचाव कार्य के लिए कोई पक्की योजना हमारे पास नहीं है। इसी वजह से विदेश से मदद लेनी पड़ी। अच्छा यही होगा कि इस घटना से सबक लेकर इस तरह के बचाव कार्य की पुख्ता प्रक्रिया और सामर्थ्य देश के पास हो ताकि आने वाले वक्त में इस तरह का बचाव कार्य जल्द से जल्द और बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके। इस हादसे से सबक लेते हुए आपदा प्रबंधन कार्यों को आधुनिक रूप देने के लिए हर संभव उपाय किए जाने चाहिए। विदेशों से हम तकनीक के मामले में मदद लेते रहते हैं। इस क्षेत्र में भी विदेशों से तकनीकी ज्ञान हासिल करने के साथ इंजीनियरों के प्रभावी प्रशिक्षण की भी समुचित व्यवस्था नियमित रूप से होनी चाहिए। विशेषज्ञों की मानें, तो अब भारत में सुरंग निर्माण पहले से कहीं ज्यादा चाक–चौंबद हो जाएगा। सिलक्यारा में सत्रह दिन के अंधेरे के बाद आई नई सुबह से भले ही हर भारतीय खुश हुआ होगा, लेकिन असली खुशी तो तब होगी जब ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सिलक्यारा हादसे से नकारात्मक नजरिया बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तय सुरक्षा प्रोटोकॉल को और सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। निश्चित ही अपने बुलंद हौसलों के कारण सिलक्यारा बचाव अभियान में हम कामयाब होकर पूरी दुनिया के सामने एक प्रेरणा बन गए हैं।

राजस्थानी राजनीति के अपरिहार्य चेहरे हैं अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे

संसदीय लोकतंत्र में सत्ता की कमान जिन्हें मिलती है, उनका सबसे बड़ा आधार राजनीतिक दल हैं। दिलचस्प यह है कि जिस लोकप्रतिनिधित्व कानून के जरिए देश में चुनाव होते हैं, उनमें राजनीतिक दल का जिक्र तो है, लेकिन राजनीतिक दलों की बात संविधान में कहीं नहीं है। संसदीय राजनीति के केंद्र बिंदु बने राजनीतिक दलों के लिए तय है कि उनमें अंदरूनी लोकतंत्र रहे और चुनाव होते रहें। लेकिन देश के तकरीबन सभी दलों में अंदरूनी लोकतंत्र की सिर्फ रस्म निभाई जाती है। अव्वल तो हर दल में अपना–अपना शक्तिशाली केंद्रीय नेतृत्व उभर चुका है। केंद्रीय नेतृत्व की ही मर्जी पर राज्यों के क्षत्रपों का नाम राजनीतिक दल तय करते हैं। केंद्रीय नेतृत्व की आंख से उतरा नहीं कि स्थानीय नेतृत्व किनारा हो जाता है।

लेकिन अपने देश में एक राज्य ऐसा भी है, जहां इस परिपाटी को चुनौती मिल रही है। इस राज्य में प्रमुख रूप से देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का ही दबदबा है। लेकिन दोनों ही दलों के पास इस राज्य में एक ऐसा स्थानीय नेतृत्व है, जो अपने–अपने दलों के शक्तिशाली केंद्रीय नेतृत्व को परोक्ष रूप से चुनौती दे रहा है। अव्वल तो दूसरा कोई होता तो दोनों ही दल अपने इन नेताओं को किनारे लगा चुके होते। लेकनि इनकी स्थानीय स्तर पर ताकत ऐसी है कि मौजूदा विधानसभा चुनावों में दोनों ही दलों को अपने स्थानीय ताकतवर नेतृत्व को नकार पाना संभव नहीं रहा।

आपके मन में सवाल होगा कि आखिर वह कौन–सा राज्य है, जहां दोनों दलों में ऐसा स्थानीय नेतृत्व है, जिसे अपने केंद्रीय नेतृत्व की परवाह नहीं है। कुछ लोग अनुमान लगा भी रहे हैं। जी हां, आपने ठीक फरमाया, वह राज्य राजस्थान है। और यहां के दोनों दलों के स्थानीय क्षत्रप इतने ताकतवर हैं कि उनके बिना दोनों ही दल अपनी स्थानीय राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते। एक तरफ हैं कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो दूसरी तरफ हैं भाजपा की नेता और दो बार मुख्यमंत्री रह चुकीं वसुंधरा राजे सिंधिया। दोनों नेताओं की अपने–अपने समर्थक आधार पर पकड़ ही है कि दोनों ही दल अपने इन नेताओं को नकारने की हिम्मत नहीं दिखा सके। अशोक गहलोत से उनके पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के सुपर आलाकमान राहुल गांधी की नाराजगी की खबरें दिल्ली से लेकर जयपुर तक के सियासी वायुमंडल में फैली हुई हैं। राजस्थान के चुनाव प्रचार में इसका असर दिखा भी। राज्य में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद राहुल गांधी महज चार धंटे के लिए राजस्थान पहुंचे और तीन जनसभाओं को संबोधित किया। राजस्थान में विधानसभा की दो सौ सीटें हैं, लेकिन राहुल गांधी की तीन जनसभाओं के केंद्र में महज डेढ़ दर्जन ही विधानसभा सीटें रहीं।

जिन्हें पता है कि कांग्रेस के सुपर आलाकमान इंदिरा परिवार की क्या ताकत होती है, वे जानते हैं कि अगर गहलोत की ताकत नहीं होती तो अब तक उन्हें आलाकमान घुटनों के बल ला चुका होता। लेकिन आलाकमान ऐसा नहीं कर पा रहा है। याद कीजिए, सचिन पायलट के विद्रोह को। उनके विद्रोह के वक्त कांग्रेस आलाकमान चाहता था कि अशोक इस्तीफा दें। आलाकमान का संदेश लेकर कांग्रेस के दो दूत मल्लिकार्जुन खरगे और अजय माकन जयपुर पहुंचे, लेकिन गहलोत ने ना सिर्फ इससे इनकार कर दिया, बल्कि शांति धारीवाल की अगुआई में विधायकों ने अशोक नहीं तो कोई नहीं जैसा समानांतर बगावत कर दी। अशोक गहलोत नहीं माने और अपने दम पर सचिन पायलट का विद्रोह थामने में कामयाब रहे।

उसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनकी जगह पर वे खड़गे अध्यक्ष बनाए गए, जो कभी उनके खिलाफ हुई बगावत को थामने के लिए आलाकमान के दूत बनकर जयपुर पहुंचे थे। कांग्रेस आलाकमान शांति धारीवाल को टिकट नहीं देना चाहता था, लेकिन गहलोत उन्हें टिकट दिलाने में कामयाब रहे। आलाकमान रोक नहीं पाया। जिन्हें सोनिया गांधी की राजनीति पता है, उन्हें पता है कि अपने विरोधियों को वे माफ नहीं करतीं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उस दौर में एक घोटाले को लेकर संसद में केरल के नेता केपी उन्नीकृष्णन ने सवाल उठाया था। उस दौर में उनके नाम से मिलते–जुलते नाम वाले एक और नेता थे, पी उपेंद्र। पी उपेंद्र बाद में वीपी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री बने। उपेंद्र तेलुगू देशम के सांसद थे। सोनिया घोटाला उठाने को लेकर केपी उन्नीकृष्णन से खफा थीं, लेकिन वह उपेंद्र और उन्नीकृष्णन में फर्क नहीं कर पाईं। आंध्र के एक दौरे से पति राजीव के साथ लौटते वक्त उन्हें उपेंद्र दिख गए और उन्हें उन्होंने सार्वजनिक रूप से हड़का दिया था। शांति धारीवाल ने बगावत के दिनों में प्रेस से यहां तक कह दिया था कि कौन हैं सोनिया गांधी। माना जा रहा था कि शांति धारीवाल के राजनीति के दिन लद गए, लेकिन अपने इस वफादार को अशोक गहलोत टिकट दिलाने में कामयाब रहे या दूसरे शब्दों में कहें तो टिकट उन्होंने दिया, यह जानते हुए भी उनका सुपर आलाकमान उनसे नाराज है।

अब बात करते हैं वसुंधरा की। राजस्थान में वसुंधरा खुद को बीजेपी की सर्वोच्च नेता मानती रही हैं। वे सिर्फ अटल और आडवाणी के सामने झुकती रही हैं। अन्यथा वे किसी के सामने नहीं झुकतीं। याद कीजिए 16 मई 2014 की तारीख को, जब भाजपा इतिहास बनाने जा रही थी। पहली बार केंद्र में अपने दम पर सरकार बना रही भाजपा की क्षत्रप वसुंधरा नाराज होकर राजस्थान की सभी 25 सीटों से जीते भाजपा सांसदों को लेकर दिल्ली के राजस्थान हाउस चली गई थीं। इसके पहले केंद्रीय नेतृत्व के आदेश के बावजूद उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया था। राजस्थान में इस बार माना जा रहा था कि वसुंधरा पहले की तुलना में कमजोर हुई हैं, इसलिए वे अपनी उपेक्षा से बगावत कर सकती हैं। लेकिन वसुंधरा ने खुलकर तेवर नहीं दिखाए। लेकिन पर्दे के पीछे वे सक्रिय रहीं।

राजस्थान में कहा जा रहा है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को लगा कि अगर वसुंधरा को नहीं साधा गया और वे कुछ ऐसा–वैसा कदम उठा लेंगी तो राजस्थान में उसकी सत्ता की उम्मीदें धूमिल पड़ जाएंगीं। इसलिए उन्हें मनाने की कोशिशें पर्दे के पीछे से चलीं। वसुंधरा ने तेवर नहीं दिखाए। कहा जा रहा है कि पार्टी उन्हें राजस्थान के लिए अपरिहार्य मानने को मजबूर हुई। राजस्थान में तो यहां तक कहा जा रहा है कि पार्टी ने करीब तीस फीसद टिकट उनके ही समर्थकों को दिए हैं। वैसे उनके कई समर्थक बागी बनकर मैदान में ना सिर्फ डटे रहे, बल्कि भाजपा के लिए परेशानी का सबब बनते रहे।

चाहे बात अशोक की हो या वसुंधरा की, दोनों ने साबित किया है कि वे अपनी–अपनी पार्टियों के लिए राजस्थान में अपरिहार्य हैं। अशोक गहलोत वैसे तो बेहद विनम्र हैं, लिहाजा उनके तेवर में भी विनम्रता रहती है। राजस्थान की कांग्रेसी राजनीति में वे तेवर में हैं। लेकिन उन्होंने विनम्रता नहीं खोई है। इसलिए उनके तेवर को सामान्य नजरों से नहीं देखा जा रहा है। लेकिन असलियत में वे अपने आलाकमान के खिलाफ तेवर में ही हैं। वसुंधरा का स्वभाव तेवर वाला रहा है, लेकिन इस बार उन्होंने तेवर ना दिखाकर विनम्रता का दामन थाम लिया है। हालांकि उनके कदमों से उनके तेवर की छाप दिखती रही है। राजस्थान में कहा जाता है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे भले ही दो विपरीत वैचारिक धाराओं वाली पार्टी के अगुआ हों, लेकिन दोनों में अंदरखाने में दोस्ती है। दोनों एक–दूसरे का लिहाज करते हैं। जिस तरह अपनी–अपनी पार्टियों में ये अपरिहार्य बने हैं और तेवर दिखा रहे हैं, उससे क्या यह मान लिया जाए कि उनकी रणनीति में उनकी दोस्ती भी दिख रही है? इस सवाल का जवाब हमें वक्त पर छोड़ देना चाहिए।

खालिस्तानियों की शर्मनाक हरकत

भारत से राजनयिक विवाद के बावजूद जहां कनाडा में खालिस्तान समर्थकों का उत्पात जारी है वहीं अमेरिका के न्यूयार्क में गुरुपर्व के मौके पर गुरुद्वारे में माथा टेकने गए भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह घ्संधू से खालिस्तान समर्थकों की धक्का–मुक्की और शर्मनाक व्यवहार की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। खालिस्तान समर्थकों ने उन्हें आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए नारेबाजी की और आरोप लगाया कि उन्होंने ही एसएफजे के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश भी रची है। कनाडा में खालिस्तानी तत्व लगातार हिन्दू मंदिरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और पन्नू ने तो यह धमकी भी दी है कि कनाडा से हिन्दुओं को निकाला जाना चाहिए। पन्नू ने हाल ही में एयर इंडिया के विमानों को निशाना बनाने की धमकी दी थी और वह लगातार भारत के विरुद्ध जहर उगल रहा है। पन्नू अमृतसर के गांव खानकोट का रहने वाला है और वह अमेरिका में रहकर पंजाब में खालिस्तानी अलगाववादी मुहिम चला रहा है। भारत ने उसे आतंकवादी घोषित कर रखा है और उस पर एक दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। वह कथित खालिस्तान की स्थापना को लेकर डींगे हांकता रहता है। एक आतंकी इतना प्रभावशाली हो चुका है घ्जो कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय को धर्म के आधार पर घविभाजित करने की कोशिश कर रहा है। कनाडा में मुट्ठी भर खालिस्तान समर्थकों ने मंदिर के सामने प्रदर्शन किया तो हिन्दू समुदाय के लोग भी उनके सामने खड़े हो गए। जब भारत माता की जय के नारे गूंजे तो खालिस्तान समर्थक भाग खड़े हुए। न्यूयार्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मेंभारत की भूमिका को लेकर जो आरोप लगाए है, अमेरिका ने ही इस मामले में उन्हें खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई थी। हाल ही में अमेरिकी अखबार फाइनैंशियल टाइम्स ने भी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि अमेरिका ने अपने देश की भूमि पर गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को नाकाम किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इस साजिश में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया है। इसके बाद अमेरिका की भूमिका को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं कि अमेरिका भारत से कैसे रिश्ते रखना चाहता है। पन्नू को अमेरिका की नागरिकता हासिल है और इन रिपोर्टों का अर्थ यही है कि उसे कनाडा और अमेरिका की सरकारों का संरक्षण प्राप्त है। अमेरिका ने तो भारत को यहां तक कह दिया था कि वह आतंकवादी निज्जर की हत्या की जांच में कनाडा को सहयोग करेगा। हैरानी इस बात की है कि जिस अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन की तलाश में अफगानिस्तान की तेरा बोरा पहाड़ियों की खाक छानी और अंततः पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मारा था, जिस अमेरिका ने अफगानिस्तान में छिपे बैठे अल जवाहरी को ड्रोन घमिसाइल से मार गिया और जिस अमेरिका ने इराक में घुसकर सद्दाम हुसैन को ढूंढकर फांसी पर चढ़ाया था उसे आतंकीघ निज्जर की हत्या और पन्नू पर हमले की साजिश की इतनी चिंता क्यों है? क्या कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस पर कभी सवाल उठाया था। जस्टिन ट्रूडो एक के बाद एक गलतियां कर रहे हैं, जिसके चलते कनाडा में किसी दूसरे देश की तुलना में ज्यादा आतंकी और गैंगस्टर मौजूद हैं। यह ड्रग तस्कर, आतंकवादी और गैंगस्टर आपस में लड़ रहे हैं। यह वही खालिस्तानी हैं जिन्होंने भारत के कनिष्क विमान को उड़ा दिया था, जिसमें 300 से ज्यादा कनाडाई नागरिक मारे गए थे। वहां खालिस्तान समर्थक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ट्रूडो का खालिस्तान समर्थकों से समझौता है। इसके पीछे कारण यह है कि उनकी अल्पमत सरकार कोघ्खालिस्तानी पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। अपनी अल्पमत सरकार को बचाने के लिए ही ट्रूडो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।

कनाडा में ट्रूडो की लोकप्रियता महंगाई और बेरोजगारी तथा लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के चलते घट चुकी है और वह जैसे–तैसे अपना पद बचाने केघ लिए जुगाड़ में लगे हैं। अमेरिका एक तरफ भारत से व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी बढ़ा रहा है। इसी महीने भारत और अमेरिका के बीच टू प्लस टू मंत्रीस्तर की वार्ता हुई है लेध्किन वह आतंकवाद के मामले में दोगली चाल चल रहा है। इस विवाद से यह संकेत भी मिलता है कि अगर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ा तो अमेरिका की कूटनीतिक प्राथमिकताएं क्या होंगी। हालांकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार बनकर उभरा है लेकिन तथ्य यह है कि कनाडा अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है और अमेरिका–मैक्सिको–कनाडा समझौते की बदौलत उनके पारम्परिक रिश्ते रहे हैं। एक करीबी आर्थिक और सांस्कृतिक साझेदार तथा चीन के बढ़ते प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए एक बिना जांचे परखे साझेदार के बीच चुनने में शायद अमेरिका को कोई संशय न हो। खासकर तब जब अमेरिका जापान, दक्षिण कोरिया और फिलिपींस के माध्यम से त्रिपक्षीय गठजोड़ के रूप में विकल्प तलाश रहा हो। ऐसे में कनाडा को लेकर भारत की नाराजगी उचित हो सकती है लेकिन भारत को शायद घरेलू और विदेश नीति संबंधी लक्ष्यों में संतुलन कायम करना पड़े। भारत ने इन मामलों को गम्भीरता से लिया है।

शिवपाल की मांग, बीजेपी जातीय जनगणना पर बोले,

डिप्टी सीएम का जवाब, सत्ता से बेदखल हुए तो इन्हें पिछड़े याद आ रहे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शीतकालीन सत्र का गुरुवार यानी आज तीसरा दिन है। सत्र में शामिल होने पहुंचे शिवपाल और डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने मीडिया से बात की। जातीय जनगणना पर दोनों ने एक–दूसरे पर

वार–पलटवार किया। शिवपाल ने कहा बीजेपी के पिछड़े वर्ग के सदस्य जातीय जनगणना पर बात करें। इसके जवाब में केशव बोले–जब सत्ता से बेदखल हो गए तो सपा को अब पिछड़ों की याद आ रही है। सदन में सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे डेंगू और गन्ना किसानों को लेकर चर्चा करने की मांग कर रहे थे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि आपने इसका प्रश्न काल और नोटिस नहीं दिया। इसलिए इस पर चर्चा नहीं की जाएगी। डेंगू और स्वास्थ्य को लेकर सदन के दूसरे दिन कार्यवाही में चर्चा हुई थी। आज तीसरे दिन भी सपा विधायक चर्चा करने की मांग कर रहे थे। चर्चा की बात नहीं बनी तो सपा ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने सदन के बाहर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए गुंडा अधिनियम को वापस क्यों लिया गया? आखिर राज्यपाल ने इस बिल पर क्यों सहमति नहीं दी। इस बिल को गोपनीय तरीके से सदन के पटल पर रखकर वापस ले लिया गया। लेकिन, इस पर चर्चा नहीं की गई। क्योंकि सदन की कार्यवाही में कोई भी बल सदन में पास होता है। उसकी स्वीकृति अगर राज्यपाल नहीं करती हैं तो इस पर चर्चा होती है। सरकार और सदन को बताया जाता है कि ये बिल क्यों नहीं पास हुआ। आराधना मिश्रा मोना ने यह भी कहा कि ऐसा विधानसभा के इतिहास में पहली बार होगा, जब कोई बिल वापस हुआ हो और उस पर राज्यपाल ने असहमति जताई हो। यूपी सरकार और राज्यपाल के बीच आखिर कौन–सी असमंजस की स्थिति बनी है। इस पर बिल के वापस होने को लेकर हमने आज सदन में चर्चा के लिए कहा था, लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई है। लखनऊ समेत सात महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद गुंडा एक्ट लागू करने और आरोपित की अपील करने पर उसकी सुनवाई के अधिकारों में कुछ बदलाव किए गए थे। इसी साल मार्च में कैबिनेट ने उप्र गुंडा नियंत्रण (संसोधन) विधेयक 2021 में परिवर्तन के साथ उप्र गुंडा नियंत्रण (संसोधन) विधेयक 2023 लागू किए जाने की मंजूरी दी थी। जिसके माध्यम से पुलिस कमिश्नरेट में अपील सुनने का अधिकार पुलिस आयुक्त को दे दिया गया था, जबकि उनके अधीनस्थ अधिकारियों को इसे लागू करने के अधिकार दिए गए थे। आराधना मोना ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई पेंशन स्कीम लागू किए जाने का जो प्रावधान लाया गया है। वह पूरी तरीके से स्कैम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पेंशन स्कीम लागू की है। इस स्कीम को लागू करने में सरकार द्वारा स्कैम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में इंपैलंटमेंट 12 कंपनियों में से नई पेंशन योजना का टेंडर नहीं दिया गया। आखिर वह कौन सी कंपनी है, जिसको पेंशन स्कीम लागू किए जाने का टेंडर दिया गया है। इस स्कीम में बड़ा घोटाला होगा, इसकी जांच मुख्यमंत्री द्वारा सीट से कराई जा रही है। विपक्षी दल लगातार उत्तर प्रदेश में किसान, स्वास्थ्य, बिजली और कानून व्यवस्था खराब होने का हवाला देते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी गन्ना, किसान, बेरोजगारी, डेंगू सहित कई मुद्दों पर हंगामा हो सकता है।

कर्मचारियों पर लगा 13 लाख के गबन करने का आरोप,केस दर्ज

लखनऊ। लखनऊ के सरोजनीनगर थाना क्षेत्र में स्थित एक ऑनलाइन कंपनी में कार्यरत डिलीवरी ब्वॉयज पर 13 लाख रूपये का सामान चुराने का आरोप लगा हैं। पुलिस ने कंपनी के नोडल ऑफिसर की तहरीर पर कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी हैं। मैसर्स इन्स्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि (नोडल ऑफिसर) ने पुलिस से लिखित शिकायत करते हुए बताया कि मैसर्स इन्स्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पूरे लखनऊ प्रदेश में उपभोक्ताओं के ऑनलाइन मांग के अनुसार सामान उपलब्ध करवाती है। कंपनी का व्यवसाय ई–कार्ट के माध्यम से संचालित होता है। कंपनी के वितरण कर्मचारी इस व्यवसाय में मुख्य भूमिका निभाते है। राम सागर का कहना है कि डिलीवरी ब्वॉयज धीरज सिंह निवासी नहरौली अदुकी मथुरा, कौशल कुमार पांडे निवासी भोलेपुर फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, रामकृष्ण निवासी बरमेन्द्रकपुर बिलाल , बंदायू और गोविंद निवासी चांदपुर फर्रुखाबाद ने सामान वितरण कर्मचारी के तौर पर कंपनी के कीमती सामान को उपभोक्ताओं को ना देकर खुद गबन करके कंपनी से फरार हो गए हैं। जिस कारण कंपनी पर आर्थिक संकट टूट पड़ा है। उच्च मूल्य के मोबाइल फोन, घड़ी और ऐरपोडस आदि शामिल है। इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए वह उपभोक्ताओं द्वारा वापस किये गए सामान की नकली सामान व पत्थर, साबुन जैसी वस्तुओं से अदल बदल कर कंपनी को सौंप देते है। इसके अलावा यह अपराधी कंपनी का 13 लाख रूपये की एप्पल घड़ी और ऐरपोडस हब से चुरा कर ले गए है। यह लोग हब से आए सामान को छुपा कर हब से बाहर ले जाते थे। जब तक इस बात खुलासा होता की सामान के साथ हेरा फेरी की गयी है। उससे पहले वह सब फरार हो गए। रामसागर का अंदेशा है कि गबन और चुराए गए मोबाइल फोन व अन्य सामान का गलत इस्तेमाल करके किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते है। सरोजनी नगर थाना प्रभारी शैलेंद्र गिरी ने बताया कि नोडल ऑफिसर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही हैं।

बेटी से सालों बाद मिले पिता,तो छलके खुशी के आंसू

झारखंड की महिला कई वर्षो से थी गायब।

लखनऊ। पति अपनी पत्नी को मानसिक स्थिति में भले ही उसे छोड़ सकता है लेकिन एक पिता के लिए बेटी हमेशा जिम्मेदारी ही रहती है। कुछ ऐसा ही मामला लखनऊ में देखने को मिला। दरअसल झारखंड के गोड्डा जिले की साधना देवी अपना मानसिक संतुलन खोने के बाद घर से भटक कर लखनऊ आ गई। यहां सड़को पर कई वर्षो से इधर उधर लावारिस स्थिति में भटकती रहीं। इसी दौरान उनके पैर के तलवे में गंभीर घाव हो गया था। समाजसेवी एवं अधिवक्ता ज्योति राजपूत की नजर इन पर पड़ी तो उन्होंने साधना देवी को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया एवम इलाज शुरू करवाया। बीच में महिला अस्पताल से भाग गई थी लेकिन पुनः आ गई थी। महिला का 20 दिन तक चला । पैर का घाव ठीक होने के पश्चात अधिवक्ता ज्योति द्वारा सूचना मिलने पर सोशल एक्टिविस्ट बृजेंद्र बहादुर मौर्य द्वारा साधना देवी की आवश्यक डिटेल्स लेकर झारखंड में परिवार खोजने की मुहिम शुरू हुई। सोशल मीडिया की मदद एवम अन्य संसाधनों के सहयोग से झारखंड गोड्डा जिले से साधना देवी के पिता का संपर्क मिला। जिसके पश्चात गुरुवार को सिविल अस्पताल में मेडिकल प्रक्रिया पूरी करने के बाद एक परिवर्तन फाउंडेशन के अध्यक्ष ज्ञान तिवारी द्वारा साधना देवी को उनके पिता के साथ झारखंड रवाना कर दिया गया। अधिवक्ता ज्योति राजपूत एवम सोशल एक्टिविस्ट बृजेंद्र बहादुर मौर्य संयुक्त रूप से ऐसे केसेस में घर से गायब लोगो के परिवार का पता करके उनके घर उन्हे वापस भिजवाते हैं। इससे पहले भी झारखंड, बिहार, यूपी सुल्तानपुर एवं अन्य कई जगह के भटके बुजुर्गो को उनके परिवार से मिलाया गया है। सिविल हॉस्पिटल के सीएमएस डॉ राजेश श्रीवास्तव,वार्ड इंचार्ज रेखा उपाध्याय,स्टाफ नर्स मंशा शानू,ज्योति पांडे,सुमन कुमारी, निदा खातून,भानुमति का विशेष सहयोग रहा। वार्ड आया प्रियंका, अनीता,मांडवी,सरिता एवम रामावती के द्वारा लगातार साफ सफाई पर ध्यान देने के कारण ही साधना देवी के पैरो के घाव जल्दी भर गए।

पुलिस और बदमाशों में जमकर चली गोलियां,एक के पैर में लगी गोली, दूसरा हुआ फरार

बांदा। जिले में नकाब पोस बदमाशों द्वारा असलहे के दम पर लूट की घटना काफी समय बाद सामने आई थी, जिससे जनपद में एक बार फिर असुरक्षा को लेकर दहशत का माहौल था। लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बदमशों का पता लगा लिया और जब उनकी घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी बचाव में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमे एक आरोपी घायल हो गया और गिर पड़ा वहीं दूसरा आरोपी फायरिंग करते हुए फरार हो गया। आपको बता दे पूरा मामला बदौसा थाना क्षेत्र का है जहां बीते दिन मजदूर ठेकेदार को गोली मारकर बदमाशों ने लूट लिया था इसके बाद से पुलिस एक्टिव थी और आसपास के थानों की पुलिस की टीम बनाई गई थी जो लगातार बदमाशों की तलाश कर रही थी तभी पुलिस को सूचना मिली कि लोड की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी चकिया पुल के पास मौजूद है। इसके बाद पुलिस फोर्स ने कांबिंग की तभी बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी बचाव में पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया और फायरिंग की इस मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई जिससे वह जमीन पर गिर गया वही दूसरा आरोपी फायरिंग करते हुए फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया कि आरोपी जीतू के पास से लूट के 51000 रुपए बरामद हुए हैं और लूट में प्रयोग की हुई बाइक भी बरामद कर ली गई है वही अब घायल आरोपी से पूछताछ की जाएगी जिसमें पता चलेगा की इस वारदात में और कौन–कौन शामिल है। वहीं पुलिस ने पीड़ित मजदूर ठेकेदार के एक साथी का भी नाम लिया है, जिससे पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने की बात कही गई है। पुलिस अधीक्षक के इस इशारे से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस लूट में मजदूर ठेकेदार के साथी का भी हाथ था, जिसके निशानदेही में बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया रहा होगा। हालांकि क्या हकीकत है यह पुलिस की पूरी जांच के बाद ही सामने आएगा।

विधानसभा सत्र के बाद मंत्रिमंडल विस्तार संभव

राजभर जा रहे दिल्ली, शाह से करेंगे भेंट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार की रूपरेखा तय होगी। मंत्री कौन बनेगा इन नामों पर कमोवेश सहमति बन चुकी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह से होनी है। इस मुलाकात में विस्तार की तिथि पर भी मुहर लग जाने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल विस्तार में विलंब होने पर ओम प्रकाश राजभर का यह बयान आने कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों से फोन आ रहे हैं। इसे भाजपा नेतृत्व ने गंभीरता से लिया है। सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय गृहमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने ओम प्रकाश राजभर को दिल्ली आने को कहा है। इस बाबत पूछे जाने पर ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर भाजपा नेतृत्व की नीति स्पष्ट है।अमित शाह के साथ बैठक व मुलाकात के बाद विस्तार की तिथि घोषित हो जाएगी। बताया जा रहा है कि विस्तार में ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना तय है। दारा सिंह चौहान और एक–दो और चेहरे मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं।पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को गाजीपुर से चुनाव लड़ाने का मुद्दा उछालने के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यह उनकी अपनी राय है।बृजेश सिंह का नाम चर्चाओं में लाने के लिए भाजपा के किसी नेता ने उनसे नहीं कहा।राजभर का कहना है कि भाजपा नेतृत्व कहेगा तो वह बृजेश सिंह को चुनाव में अपनी पार्टी का सिंबल दे देंगे।बृजेश सिंह गाजीपुर चंदौली से मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं।

लोहिया संस्थान का तीसरा स्थापना दिवस,

डिप्टी सीएम ब्रजेश बोले, यहां से निकले बच्चे दुनिया में नाम कमा रहे

लखनऊ। लखनऊ के गोमतीनगर स्थिति डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का स्थापना दिवस समारोह गुरुवार को मनाया गया। आईजीपी में आयोजित हो रहे वार्षिक स्थापना दिवस समारोह में डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री

ब्रजेश पाठक पहुंचे। ब्रजेश पाठक ने कहा–उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश के साथ नेपाल का भी भार पीजीआई और केजीएमयू पर था। इसी मकसद से लोहिया संस्थान को विकसित किया गया। यहां से निकले बच्चे देश दुनिया में मेडिकल फील्ड में नाम कमा रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा– सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल रहें। 65 मेडिकल कॉलेज पर काम हो रहा, 16 रह गए हैं, वहां भी काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज बनाने में मदद की है। ब्रजेश पाठक ने कहा– सरकारी कॉलेजों में डठठै में 3800 सीट और निजी कॉलेज में 5450 सीट हैं। इसके अलावा एम्स रायबरेली में 100 सीट और एम्स गोरखपुर में भी डठठै की 125 सीट हैं। 2017 से पहले जितनी सीटें थीं, अब लगभग दोगुनी सीटें बढ़ाकर कर दी गई हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा यूपी आयुष्मान कार्ड बनाने में देश में नंबर वन है। प्रदेश में साढ़े 4 करोड़ से ज्यादा कार्ड बना चुके हैं। 2017 से पहले नर्सिंग कॉलेज खुल जाते थे, लेकिन उनमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता था। डब्लयू के मानक पर हम काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देशभर के अस्पतालों को यूपी प्रोफेशनल और क्वालिफाइड नर्स प्रोवाइड करेगा। प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा–14 सरकारी मेडिकल कॉलेज अगले साल से शुरू करना होगा। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दशकों तक यूपी में महज 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम चलता था। यहां की फैकल्टी से मेरा यही कहना है कि अब उनको अपने डिपार्टमेंट से आगे बढ़कर भी सोचना चाहिए। ये कह सकते हैं कि यूपी फिलहाल इन 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर लगातार फोकस कर रहा है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और महानिदेशक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सचिव राजीव कुमार बहल ने कहा मेरा ये कहना है कि संस्थान से 50 यंग प्रोफेशनल को पीएचडी भी करना चाहिए। आईसहएमआर से रजिस्टर करने के बाद पीएचडी करने के बाद 30 लाख का ग्रांट मिलेगा। यदि 10 से 20: के करीब क्लीनिकल फैकल्टी ने भी पीएचडी करना शुरू कर दिया तो ये बड़ा बदलाव आएगा। आप अच्छी प्रैक्टिस करिए पर रिसर्च को मत भूलिए। भारत को विकसित बनाने के लिए और पीएम के जय अनुसंधान को साकार रूप देने के लिए रिसर्च बहुत जरूरी है। इसलिए रिसर्च पर फोकस जरूर करिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नीति आयोग के सदस्य डॉ. विनोद बहल रहे। 7 लोगों को रिसर्च के लिए मेडल दिया गया...डॉ. अर्पिता सिंह, डॉ. दिनकर कुलश्रेष्ठ, डॉ. सौम्या शुक्ला, डॉ. अनुराग अग्रवाल, डॉ. शिप्रा डोभाल, डॉ. रंजीत सिंह, शताक्षी संगल। 5 डॉक्टर को पेटेंट के लिए अवार्ड दिया गया...डॉ. सौम्या शंकर नाथ, डॉ. मोहम्मद कैफ, डॉ. स्वागत महापात्रा, डॉ. नेहा ठाकुर डॉ. ज्योत्स्ना अग्रवाल।

यातायात माह का समापन,उत्कृष्ट कार्य करने वालों को एसपी ने किया सम्मानित

उरई/जालौन। जालौन में आज यातायात माह का समापन हो गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने यातायात माह नवंबर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अलग–अलग विद्यालयों के छात्र– छात्राओं और पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही सभी को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके इस दौरान उन्होंने कहा कि छात्र–छात्राएं अपने परिजनों को यातायात के बारे में बताएं, जिससे उन्हें दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखा जा सके। वहीं शहर में लगाई गई ट्रैफिक लाइटों का पालन न करने वालों के 1 दिसंबर से ऑनलाइन चालान शुरू कर दिए जाएंगे। उरई के ब्रिज कुंवर देवी एल्ड्रिच पब्लिक स्कूल में आयोजित यातायात माह के समापन के अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने सभी लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करते हुए छात्र–छात्राओं ने कहा कि सभी लोग बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें। इसके साथ ही कार चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाए, इसके अलावा मोबाइल फोन पर बात करते समय, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, जिससे वह दुर्घटनाओं से बच सकते है और लोगों की जान को बचा सकते हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने कहा कि 30 दिनों तक अलग–अलग स्कूलों में तथा अन्य माध्यमों से लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही शहर में एक अलग व्यवस्था ट्रैफिक लाइट की गई है, जिसमें सभी लोगों ने प्रशासन का सहयोग करते हुए नियमों का पालन किया। वहीं सभी से उम्मीद रखेंगे कि ट्रैफिक लाइटों का अवश्य पालन करेंगे, जिससे वह जागरूक हो सके। वहीं उन्होंने यातायात माह नवंबर में लोगों को जागरूक करने वाले मिजपा क्रिश्चियन स्कूल, रामजी लाल पांडे गर्ल्स इंटर कॉलेज, मॉर्निंग स्टार, एल्ड्रिच पब्लिक स्कूल के छात्र–छात्राओं और यातायात पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। बता दें कि उरई शहर के तीन चौराहों पर ट्रैफिक लाइटें लगाई गई हैं। इन ट्रैफिक लाइटों का उल्लंघन करने पर कहा कि 1 दिसंबर से ऑनलाइन चालान शुरू कर दिए जाएंगे। इस यातायात माह कार्यक्रम के समापन के अवसर पर एल्ड्रिच पब्लिक स्कूल के प्रबंधक अजय कुमार इटौदिया, युद्धवीर कंथरिया, ममता स्वर्णकार, शशि सिंह, सुविधा इटोरिया मौजूद रहीं।

महिला ने जहर खाकर दी जान

बांदा। घरेलू किसी नाराजगी की वजह से महिला ने जहर खा लिया। बच्चों द्वारा पिता को बताने पर घर पहुंचे पति ने दरवाजा खोलवाकर उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिल्ला थाना क्षेत्र के पपरेंदा गांव निवासी रोशनी (35) ने बुधवार की रात अपने घर में जहर खा लिया। कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। काफी देर तक उसके बच्चे दरवाजा खटखटाते रहे। जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो वह पिता को बुलाने उसकी दुकान गए। बच्चों से जानकारी मिलने पर पति विनीत लखेरा दुकान से आया और काफी देर वह भी दरवाजा खटखटाता रहा। काफी देर बाद रोशनी ने दरवाजा खोला तो उसके हाथ जहर की शीशी थी। आनन फानन विनीत उसे लेकर बांदा जिला अस्पताल आया। यहां देर रात डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। पति विनीत ने बताया कि वह शराब के ठेके के पास चखने की दुकान करता है। उसके दो बेटी व एक बेटा है। रोशनी ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया उसे नहीं पता। उसने बताया कि उसके बड़े भाई सुनील की पांच साल पहले मौत हो गई थी। जिस पर उसने भाभी रोशनी से शादी की थी। बड़े भाई से एक पुत्री एक पुत्र है। उससे एक पुत्री है। डॉक्टरों ने शव को मोर्चरी में रखा दिया है।

शक में पत्नी का गला काटकर मार डाला

अलीगढ़। जिले में पत्नी पर शक करने वाले एक पति ने बेडरूम में उसकी गला काटकर हत्या कर दी। पति मौके से फरार हो गया। वहीं मां की चीख सुनकर 8 साल की बेटी दौड़कर कमरे में पहुंची तो मां लहूलुहान जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। बच्ची ने आवाज देकर घर के लोगों को वहां बुलाया। आनन–फानन में पुलिस को बुलाया गया। महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये वारदात कोतवाली इलाके के भुजपुरा की है। पुलिस ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी पति राजू फरार है। उसकी तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। राजू की 15 साल पहले सागरा से निकाह हुआ था। पारिवारिक विवाद में हत्या की बात सामने आ रही है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। महफूजनगर निवासी नजर मोहम्मद ने बताया कि उनकी छोटी बहन सागरा का निकाह लगभग 15 साल पहले भुजपुरा इलाके के राजू से हुआ था। शादी के बाद उनके दो बच्चे भी हैं। भाई ने बताया कि बुधवार शाम को उन्हें रिश्तेदारों से ही पता कि आपके बहनोई ने आपकी बहन की हत्या कर दी है। इसके बाद वह भाग गया। इसके बाद हम लोग सीधे बहन के ससुराल पहुंचे। घर के अंदर वाले कमरे में बहन का शव पड़ा हुआ था और पुलिस मौजूद थी। भाई ने बताया कि उसका बहनोई कोई जॉब नहीं करता था। उसकी बहन ही मजदूरी करके घर चलाती थी। बहनाई राजू को शक था कि उसकी पत्नी के संबंध उसके बड़े भाई से हैं। इसको लेकर दोनों के बीच झगड़े भी होते थे। लेकिन, ये नहीं सोचा था कि मामला हत्या करने तक पहुंचा जाएगा। घटना के समय सागरा की 8 साल की बेटी घर पर ही थी। राजू ने हत्या करने से पहले उसको छत पर भेज दिया और फिर अपनी पत्नी को मार डाला। मां की चीखें सुनकर जब मासूम नीचे आई तो उसने देखा कि उसकी मां बिस्तर पर पड़ी हुई है। हर तरह खून ही खून है। मासूम ने बताया कि उसके अब्बू आए दिन उसकी मां से झगड़ा करते थे। बुधवार को भी झगड़ा हुआ था। घटना की जानकारी होने पर कोतवाली पुलिस के साथ ही एसपी सिटी मृगांग शेखर पाठक मौके पर पहुंचे। पुलिस के साथ ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस को मौके से हत्या करने के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार नहीं मिला है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी मौके से फरार हो गया और और उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। सीओ प्रथम अभय कुमार पांडेय ने बताया कि घटना के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसपी सिटी ने पुलिस की 3 टीमों का गठन किया है, जो आरोपी की तलाश कर रही हैं। अलीगढ़ के बॉर्डर एरिया को सील किया गया है। ताकि राजू बाहर न भाग सके।

अनुपूरक बजट: बीजेपी का मिशन 80

महिलाओं को साधने की कोशिश, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर फोकस

लखनऊ,(यूएनएस)। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के पहले अनुपूरक बजट में विकास के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को धार के लिए खजाना खोला है। प्रदेश की सभी 80 संसदीय सीटों पर भगवा लहराने की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है।एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने राममंदिर और राष्ट्रवाद के एजेंडे का इस्तेमाल किया। श्रीराम जन्मभूमि पर जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर गांवों में रामोत्सव के आयोजन से माहौल को राममय बनाने की योजना है। चुनावी राज्यों में यूपी के सीएम योगी जहाँ जहाँ गए, रामलला के दर्शन का न्यौता दे आये हैं। श्रीराम अवतरण कॉरिडोर की घोषणा कर सरकार ने रामभक्तों को साधने का प्रयास किया है। संघ के अनुषांगिक संगठनों की मांग के अनुरूप पुराने मठ, मंदिर और धर्मशालाओं के जीर्णोद्धार पर ध्यान है। योगी सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा देकर नारी शक्ति को संदेश दिया है कि उनकी सुरक्षा के साथ सुविधाओं के प्रति सरकार चिंतित है। किसानों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए सरकार ने निजी नलकूपों के बिजली कनेक्शन पर मुफ्त बिजली देने का संकेत दिया है। सरकार ने इस एक फैसले से लाखोंकिसानों में भी अपना आधार बढ़ाने की कोशिश की है। संकेत साफ है कि 2024 के चुनावों के लिए राम, किसान और महिलाएं सत्ताधारी दल के एजेंडे में सबसे ऊपर होंगे।अनूपूरक बजट में पीडब्ल्यूडी को 4200 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसमें से तीन हजार करोड़ रुपये सड़कों की मरम्मत पर खर्च होंगे। औद्योगिक क्षेत्रों में पीडब्ल्यूडी के जरिये विकास कार्य कराने के लिए 250 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अनुपूरक बजट में स्टेट हाईवे, प्रमुख जिला मार्गों व अन्य जिला मार्गों की विशेष मरम्मत के लिए 1500 करोड़ रुपये मिले हैं। ग्रामीण मार्गों की विशेष मरम्मत के लिए भी 1500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। राज्य सड़क निधि के चालू कार्यों को पूरा करने के लिए 250 करोड़ और पुराने चालू कार्यों की चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण मद में भी 250 करोड़ रुपये दिए गए हैं।गन्ना विभाग की कुछ सड़कें हाल ही में पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर की गई हैं और उनकी सामान्य मरम्मत के लिए विभाग को 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में सेतुओं के निर्माण के लिए 52 करोड़ रुपये और प्रमुख जिला व अन्य जिला मार्गों के नए कामों के लिए 106 करोड़ रुपये दिए गए हैं।ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश के 22,339 मजरेविद्युत विहीन हैं। इनके विद्युतीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 338 करोड़ रुपये की परियोजना मंजूर की है, केंद्र सरकार ने 203 करोड़ का अंशदान भी दिया है। यहां जल्द विद्युतीकरण किया जाएगा। विधानसभा में बुधवार को सपा विधायक डॉ. मुकेश वर्मा के कई मजरों में बिजली नहीं पहुंचने के सवाल का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में डेढ़ लाख से अधिक मजरों में बिजली नहीं थी। सात साल में सवा लाख मजरों तक बिजली पहुंची है। पहले ग्रामीणों को अपने खर्च पर ट्रांसफार्मर बदलना पड़ता था, वहीं अब सरकार खुद ट्रांसफार्मर बदल रही है। 7400 ट्रांसफार्मर का उच्चीकरण किया गया है, 1130 ट्रांसफार्मर नए लगाए गए हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली का बिल बकाया होने पर किसानों की बिजली नहीं काटी जा रही है। शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक बिल बकाया होने पर ही बिजली काटने के निर्देश दिए गए हैं।

ट्रेन से गिरकर युवक की मौत, नोएडा का रहने वाला था मृतक

अलीगढ़। जिले के सोमना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। युवक नोएडा का रहने वाला था और ट्रेन में सवार होकर प्रयागराज की ओर जा रहा था। लेकिन रास्ते में ही वह ट्रेन से गिर गया और उसकी मौत हा गई। युवक का शव सोमना रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर पड़ा हुआ था। लोगों ने शव देखकर रेलवे कर्मियों को सूचना दी, जिसके बाद जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। जांच में उसकी जेब से मिले दस्तावेजों से उसकी पहचान हुई। जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव मिलने की सूचना पर खुर्जा चौकी इंचार्ज ब्रजमोहन सिंह मौके पर पहुंच गए। जब शव की जांच की गई तो उसकी जेब से कुछ कागज और पहचान पत्र पुलिस को मिला। जिसके बाद युवक की पहचान गौतमबुद्धनगर (नोएडा) के थाना जेवर के गांव कुरैब निवासी मोहित के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार कुरैब निवासी 26 वर्षीय मोहित कुमार शर्मा पुत्र जगदीश चंद्र शर्मा किसी निजी काम से ट्रेन में चढ़कर जा रहा था। लेकिन खुर्जा स्टेशन पार करने के बाद सोमना रेलवे स्टेशन के नजदीक वह ट्रेन से गिर गया, जिसके कारण उसे गंभीर चोटें आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने उसके परिजनों से संपर्क किया और उन्हें सूचना दी। जिसके बाद युवक के परिवारजन अलीगढ़ पहुंच गए और सभी का रो–रो कर बुरा हाल हो गया। युवक अपने घर का बड़ा पुत्र था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। आरपीएफ थाना प्रभारी राजीव वर्मा ने बताया कि सोमना के पास युवक का शव मिला था। युवक दिल्ली से आने वाली किसी गाड़ी में सवार था और ट्रेन से गिरकर उसकी मौत हो गई। जीआरपी ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

हत्या की साजिश रच रहे लोगों की जमानत रद्द

अलीगढ़। जिले में अपराधियों को सुपारी (रुपए) देकर गंभीर अपराध की साजिश रचने वालों की अग्रिम जमानत याचिका को न्यायालय ने रद्द कर दिया है। पुलिस की जांच में दोनों आरोपियों के नाम सामने आए थे, जिसके बाद पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही थी। पुलिस की कार्रवाई से पहले दोनों आरोपियों ने न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगा दी थी। लेकिन न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और पाया कि आवेदकों के तर्क और प्रस्तुत साक्ष्य जमानत के लिए पर्याप्त नहीं हैं। जिसके बाद विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट प्रवीण कुमार पांडेय ने दोनों की जमानत के आवेदन को रद्द कर दिया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमेंद्र जैन ने बताया कि देहलीगेट पुलिस ने 31 अक्टूबर को अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। नगला मेहताब निवासी राजकुमार पुत्र स्व. पवन कुमार की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़ित ने बताया था कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे कॉल करके गूलर रोड पर बुलाया था। फोन पर बात होने के बाद वादी राजकुमार व्यक्ति से मिलने गूलर रोड पेट्रोल पंप पर गया था। जिसके बाद उस व्यक्ति ने वादी को बताया कि कोई व्यक्ति उसे जान से मारने की साजिश कर सकता है और वह सतर्क रहे। क्योंकि कभी भी उसे जान से मारने की कोशिश की जा सकती है। इसके बाद पीड़ित ने देहलीगेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित की तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने 31 अक्टूबर 2023 को ही मुकदमा दर्ज कर लिया था। जिसके बाद पुलिस की जांच में आकाश कुमार पुत्र दिलीप कुमार निवासी नगला मेहताब, खैर रोड और लक्की सरदार पुत्र गुरमीत सिंह निवासी इंद्रानगर परी तालाब का नाम सामने आया था। दोनों आरोपियों को जब मामले की जांनकारी हुई तो इन्होंने अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में याचिका लगाई थी। आरोपियों ने न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि उन्हें रंजिशन फंसाया जा रहा है। उन्होंने किसी अपराध के लिए किसी को रुपए नहीं दिए हैं। जबकि 31 अक्टूबर को आकाश के खाते से 80 हजार रुपए निकाले गए थे। जो 2 नवंबर को वापस आ गए थे। आरोपी रुपए के आदान प्रदान की जानकारी नहीं दे पाया। न तो यह बता पाया कि वह कौन सा व्यापार करता है। आरोपियों के तर्क में संदिग्धता और गंभीर धाराओं में मुकदमा होने के चलते न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपियों से सभी तर्क को न्यायालय ने नकारते हुए यह फैसला सुनाया है।

यूपी में गुंडा एक्ट विधेयक दोनों सदनों से वापस, योगी सरकार नए सिरे से कराएगी लागू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक–2021 विधानमंडल के दोनों सदन से वापस ले लिया गया। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने तकनीकी कारणों के आधार पर विधेयक को पुनर्विचार के लिए सरकार को लौटाया था। विधानसभा में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने इसका कारण बताते हुए यह विधेयक राज्यपाल के यहां से अगस्त में वापस आया था। कमिशनरेट व्यवस्था होने से उससे में बदलाव करना जरूरी हो गया। पुलिस आयुक्त के बढ़े अधिकारों से उपजी विधिक अड़चन को लेकर उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2021 को वापस किया गया। सरकार जल्द आवश्यक बदलाव कर विधेयक को नए सिरे से लागू कराएगी ।सरकार ने इस साल मार्च माह में कैबिनेट ने उप्र गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2021 में परिवर्तन के साथ उप्र गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 लागू किए जाने की मंजूरी दी थी जिसके माध्यम से पुलिस कमिश्नरेट में अपील सुनने का अधिकार पुलिस आयुक्त को प्रदान किया गया था, जबकि उनके अधीनस्थ अधिकारियों को इसे लागू करने के अधिकार प्रदान किया गया था ।विधानसभा कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि नियम केअनुसार, सरकार को विधेयक वापस लिए जाने के कारणों को भी बताना चाहिए थे। विधान परिषद में सपा सदस्यों ने भी विधेयक वापस लिए जाने के कारणों को लेकर सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक–2021, जो राज्य विधान मंडल पारित किये जाने के बाद संविधान के अनुच्छेद–200 के अंतर्गत राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था।

सवारियों से भरी बस लेकर इमरजेंसी में घुसा ड्राइवर,

जहर खुरानी ने सवारी को कर दिया था बेहोश, अब वीडियो हो रहे वायरल

अलीगढ़। अलीगढ़ में मरीज की जान बचाने के लिए इमरजेंसी में वाहन घुसाने के एक के बाद एक दो मामले सामने आए हैं। जेएन मेडिकल कालेज के साथ ही मलखान सिंह जिला अस्पताल में भी ऐसी ही घटना हुई है। जिसमें रोडवेज बस के ड्राइवर ने सवारी की जान बचाने के लिए बस को इमरजेंसी में अंदर लगा दिया। ड्राइवर दिल्ली से बस लेकर अलीगढ़ आ रहा था और उसे बस लेकर आगे जाना था। लेकिन अलीगढ़ के कठपुला पुल पर उसे पता चला कि एक सवारी बेहोश है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। जिसके बाद ड्राइवर ने बिना सोचे समझे बस को सीधे जिला अस्पताल की इमरजेंसी में अंदर घुसा दिया। जिसके बाद मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने मरीज को उपचार देकर उसकी जान बचाई। हाथरस के कस्बा सादाबाद निवासी आशू पुत्र कोमल सिंह दिल्ली में नौकरी करते हैं। बुधवार देर रात को वह दिल्ली के लालकुंआ से हाथरस जाने के लिए बस में बैठे थे। रास्ते में उन्हें बातों में उलझाकर जहर खुरानों ने जहर दे दिया। जिसके बाद वह बेहोश हो गए। अलीगढ़ आने पर सवारियां उतरने लगी तो यह बात रोडवेज बस के कंडक्टर विनोद कश्यप को पता चली। जिसके बाद उन्होंने सवारी को जाकर देखा तो वह नशे की हालत में बेहोश पड़ा हुआ था। उन्होंने तत्काल यह बात ड्राइवर को बताई और सीधे अस्पताल चलने के लिए बोल दिया। जिसके बाद ड्राइवर ने सवारियों से भरी बस को सीधे इमरजेंसी में लगा दिया। इमरजेंसी में अचानक बस आने से अफरा तफरी मच गई। देर रात अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भौचक्का हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि कोई बड़ी घटना हुई है, जिसके कारण रोडवेज बस का ड्राइवर पूरी बस को ही इमरजेंसी के अंदर लेकर आ गया है। जब उन्हें पता चला कि जहर खुरानी ने एक व्यक्ति को जहरीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया है, तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। कंडक्टर विनोद कुमार ने बताया कि बेहोश हुए आशू के बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने अलीगढ़ तक का टिकट लिया था, लेकिन वह गभाना के पास ही उतर गया था। उन्हें संदेह है कि उसी व्यक्ति ने सवारी को जहर देकर लूट की है। वहीं होश में आने के बाद आशू ने बताया कि उनकी जेब में रखे 10800 रुपए गायब हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इंस्पेक्टर बन्नादेवी देवेंद्र त्यागी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शून्य शुल्क प्रवेश प्रणाली को खत्म करने के मुद्दे पर भड़के सपा सदस्य, विधानसभा से किया बहिर्गमन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान सभा में समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्यों ने बृहस्पतिवार को सरकार पर अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्च कक्षाओं में शून्य शुल्क प्रवेश प्रणाली के प्रावधान को खत्म कर उनके हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया। शून्यकाल में कार्य स्थगन की सूचना के माध्यम से उठे इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने आरोप लगाया कि सरकार अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित कर रही है, जिससे उन्हें और उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी नुकसान होगा। समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने अपने जवाब में कहा कि ''एक नई व्यवस्था लाई गई है। इसके तहत छात्रों को उस संस्थान की पहचान करनी होगी जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं और पोर्टल के माध्यम से अपने और संस्थान के विवरण का उल्लेख करते हुए आवेदन करना होगा। उन्हें एक फ्रीशिप कार्ड मिलेगा जिसके साथ वे प्रवेश लेने के लिए संस्थान में जा सकते हैं। इस व्यवस्था को सबसे पहले सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में लागू किया गया है। इससे जो अनुभव मिलेगा उसके आधार पर तय किया जाएगा कि क्या इसे अगले साल से निजी संस्थानों में भी ले जाया जा सकता है या नहीं। मुख्य चिंता यह संतुलन बनाने की है कि उच्च शिक्षा पाने के इच्छुक सभी लोग इसे प्राप्त कर सकें और यह भी ध्यान रखा जाए कि इसमें कोई अनियमितता न हो। सपा सदस्य लालजी वर्मा ने कहा कि पहले यह व्यवस्था थी कि अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति के छात्रों को भी शून्य प्रवेश शुल्क के माध्यम से उच्च शिक्षा मिले। मौजूदा समय में इस पर रोक लगा दी गई है। जहां पहले अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति के 25 प्रतिशत छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाते थे, वहीं अब यह संख्या घटकर 10 से नौ प्रतिशत रह गई है। ज्यादा शुल्क होने के कारण वे तकनीकी संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। इसी वजह से उनका अनुपात कम हो गया है। इसे बड़े पैमाने पर कायम रखने के लिए शून्य शुल्क प्रवेश व्यवस्था बहाल करने की जरूरत है। सपा सदस्य ने कहा कि कोई अनियमितता न हो इसके लिए इस योजना को भी आयुष्मान कार्ड की तर्ज पर चलाया जा सकता है। इन छात्रों को शिक्षा देना हमारा संवैधानिक दायित्व है क्योंकि यूपी में अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति की संख्या 23 प्रतिशत है। मगर शिक्षण संस्थानों में आबादी के मुताबिक उनकी भागीदारी नहीं है। उन्होंने इस मुद्दे पर सदन में दो घंटे की चर्चा कराने की मांग की। वहीं, सपा सदस्य रागिनी सोनकर ने कहा कि हालांकि भाजपा सरकार सबका साथ–सबका विकास की बात करती है, लेकिन यह जमीन पर नजर नहीं आती। मंत्री के जवाब पर असंतोष व्यक्त करते हुए सपा सदस्यों ने कहा कि शून्य प्रवेश शुल्क प्रणाली के बिना इन वर्गों के छात्रों के हित और अधिकार सुनिश्चित नहीं किये जा सकते। इसके बाद वे सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए।

लोकतंत्र में विधायिका की बड़ी होती है भूमिका : महाना

छात्र छात्राओं ने देखी विधानसभा की कार्यवाही, अध्यक्ष ने दी जानकारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सुल्तानपुर जिले के छात्र छात्राओं के एक दल ने विधानसभा की कार्यवाही देखी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने छात्र छात्राओं को उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही तथा इसके संचालन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष श्री महाना ने कहा कि विधानसभा केवल एक भवन नही है बल्कि यहां से जनहित के लिए कार्यों की रूपरेखा तय होती है। नवयुग इंटर कॉलेज दोस्तपुर सुल्तानपुर के 40 छात्र छात्राओं के दल ने विधानसभा की कार्यवाही को देखने के विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। उन्होंने कई सवाल किए। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें बताया कि विधानसभा का संचालन कैसे होता है। कार्यवाही के दौरान विधानसभा के नियमो के तहत ही कोई सदस्य सदन में बोल सकते हैं। एक छात्रा के सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि यहां पर उठाए गए मामले संबंधित विभाग को भेजे जाते है। संबंधित समितियां मामलों, समस्याओं को क्रियान्वित कराने का काम करती हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि लोकतंत्र में विधायिका की बड़ी भूमिका होती है। जनता का विधायक से सीधा संपर्क रहता है। इसलिए जनता उन्हें चुनकर भेजती है। जनता उसे ही भेजती है जिससे वह संतुष्ट होती है। विधानसभा में विधेयक पारित किए जाते हैं जिससे अंतर्गत कानून व्यवस्था से लेकर जनहित के विकास के काम किए जाते हैं। एक अन्य छात्रा के सवाल के जवाब में श्री महाना ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदस्यों को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। लेकिन कोई भी सदस्य विधानसभा की नियमावली के तहत ही सदन में अपनी बात रख सकता है। विधानसभा आए दल में प्रिंसिपल संदीप मिश्र,अध्यापक अध्यापिकाओं में रवि पांडे, वैशाली मिश्रा तथा गुंजा शर्मा शामिल थे।

वी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को २३००० से अधिक नोटबुक्स दान में देगा

लखनऊ। वर्तमान में चल रहे अपने कैंपेन 'बी समवन्स वी' जिसका उद्देश्य लोगों को प्यार एवं देखभाल का अहसास कराकर बेहतर आज एवं उज्जवल कल का निर्माण करना है, के मद्देनजर जाने–माने दूरसंचार सेवा प्रदाता 'वी ने 23071 नोटबुक्स का उपयोग कर दुनिया के सबसे बडे नोटबुक सेंटेंस के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।''इस पहल का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित जानेश्वर मिश्रा पार्क में किया गया, जहां वी के कर्मचारियों एवं उनके परिवारों, उम्मीद फाउन्डेशन, केयर एजुकेशन ट्रस्ट, आदिज्योति सेवा समिति और बाल शाश्वत फाउन्डेशन से 500 जरूरतमंद बच्चां सहित 700 से अधिक लोगों ने एक साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा नोटबुक सेंटेंस– 'बी समवन्स वी' बनाया और इसके माध्यम से समावेशन एवं एकजुटता का संदेश दिया।''वी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में इस्तेमाल हुई 23071 नोटबुक्स को उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्रालय को दान में देगा।' इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने का मुख्य उद्देश्य इस बात पर रोशनी डालना है कि किस तरह एक नेटवर्क पूरे समुदाय को एकजुट करता है और मानवीयध सामजिक रिश्तों को जोड़ने वाले पुल की तरह काम करता है। इसके अलावा समावेशन एवं एकजुटता की भावना को बढ़ावा देना भी इसका मुख्य उद्देश्य है।'इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री बृजेश पाठक जी भी वी की इस पहल को समर्थन प्रदान करने के लिए मौजूद रहे। उन्होंने एनजीओ के बच्चों और वी के कर्मचारियों के साथ कुछ समय बिताया और सभी को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।''कार्यक्रम में मौजूद अन्य दिग्गजों में श्रीमति बेबी रानी मौर्य, माननीय केबिनेट महिला एवं बाल विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, श्रीमति सुषमा खर्कवाल, माननीय मेयर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश भी मौजूद रहे।''इस उपलब्धि पर उत्साह व्यक्त करते हुए प्रवीण कुमार, ऑपेरशन्स डायरेक्टर, वोडाफोन आइडिया ने कहा', ''सबसे बड़े नोटबुक सेंटेंस के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की इस उपलब्धि को हासिल करते हुए हमें बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है। भारत में अकेलापन बढ़ रहा है और इस विश्व रिकॉर्ड के माध्यम से हम देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि आपका छोटा सा प्रयास किसी व्यक्ति को यह अहसास करा सकता है कि वह अकेला नही है। कोई है जो उसे प्यार देने और उसकी देखभाल करने के लिए मौजूद है। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़कर एकजुटता और समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम है। मैं लखनऊ के बच्चों और लोगों के प्रति आभारी हूं जिन्होंने इस उपलब्धि को संभव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम बच्चों के लिए 'वी' बन गए हैं और दूसरों के लिए भी एकजुटता की इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं।''वर्ल्ड रिकॉर्ड पर बात करते हुए स्वप्निल डंगारिकर, आधिकारिक निर्णायक, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' ने कहा, ''यह सबसे बड़ा नोटबुक सेंटेंस बनाने का रिकॉर्ड प्रयास था। इससे पहले यह रिकॉर्ड 2019 में 7674 नोटबुक्स के साथ बनाया गया, उस समय भी मैं निर्णायक था। आज एक बार फिर से मैंने देखा कि वोडाफोन आइडिया ने कितनी नोटबुक्स का इस्तेमाल कर यह रिकॉर्ड बनाया। नोटबुक्स और डिजाइन पहले से अनुमोदित थे। फाइनल जांच के बाद, मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 23071 नोटबुक्स के साथ वोडाफोन आइडिया ने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और सबसे बड़े नोटबुक सेंटेंस के साथ नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मैं इस उपलब्धि के लिए वी को बधाई देना चाहूंगा।''वी का मौजूदा कैंपेन 'बी समवन्स वी' यह शक्तिशाली संदेश देता है कि अच्छे–बुरे हर समय में एक दूसरे का साथ दें, आप छोटे से प्रयासों से भी दूसरों के प्रति सहानुभूति को दर्शा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसी समावेशी दुनिया का निर्माण करना है, जहां लोग अपने आप को अकेला महसूस न करें, उन्हें यह अहसास हो कि कोई है जो उनकी देखभाल करने, उन्हें प्यार करने के लिए मौजूद है।

उद्यमी महासम्मेलन में बोले योगी, कहा, एमएसएमई सेक्टर आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत

लखनऊ। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) द्वारा आयोजित उद्यमी महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 'उत्तर प्रदेश का एमएसएमई (एमएसएमई) सेक्टर आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। हमने टेक्नोलॉजी को सुदृढ़ करके इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने की

दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हुए रिफॉम के परिणाम सबके सामने हैं। पूरी दुनिया विश्वास के भाव से उत्तर प्रदेश की ओर देख रही है। हमें अभी से 2024 के इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ट्रांसफॉर्मिंग एमएसएमई टुवॉर्ड्स इंडस्ट्री 4.0 एंड स्किल 48 से संबंधित प्रदर्शनी का भी मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया, जिसमें प्रदेशभर से एमएसएमई स्टार्टअप उद्यमियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। सीएम ने आयोजकों और उद्यमियों का प्रदेश की राजधानी में स्वागत करते हुए कहा कि पहले यूपी में उद्यम के लिए माहौल और सरकार के स्तर पर प्रोत्साहन व संरक्षण ना होने पर उद्यमी हतोत्साहित था। 2017 में प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद अपने परंपरागत उत्पादों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट करने के कार्यक्रम का परिणाम हम सबके सामने है। ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक अभिनव योजना है। सीएम योगी ने उद्यमियों से आह्वान किया कि कंपटीशन के दौर में प्रोडक्ट की क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही उसकी पैकेजिंग पर और ज्यादा कार्य करना होगा। उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी को सुदृढ़ करते हुए इंस्पेक्टर राज से मुक्ति के कार्यक्रम चलाए गये हैं। निवेश मित्र पोर्टल, निवेश सारथी पोर्टल और ऑनलाइन इन्सेंटिव प्लेटफॉर्म की चर्चा करते हुए योगी ने कहा कि इससे उद्यमियों को प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाओं को विकसित करने के साथ साथ उनकी सुविधाओं के सरलीकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की रैंकिंग आज से 6 साल पहले 14 वें स्थान पर थी। इसमें व्यापक रिफॉर्म किए गये। जिसका परिणाम सबके सामने है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अंदर लैंड बैंक बनाने का कार्य हो या बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित करना हो, हर दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। फरवरी 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सितंबर में ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन भी शानदार रहा। इसमें 70 हजार बायर्स आए थे और टोटल फुटप्रिंट चार लाख थी। 400 से ज्यादा विदेशी बायर्स भी वहां पहुंचे। सभी को नए भारत के नए यूपी के पोटेंशियल को देखकर आश्चर्य हुआ। पूरी दुनिया विश्वसनीयता के भाव से भारत और यूपी की ओर देख रही है। जहां नोएडा और ग्रेटर नोएडा को विकसित करने में 46 साल लगे, वहीं वर्तमान में हम झांसी, बुंदेलखंड में एक नए औद्योगिक संस्थान की दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं। झांसी में हमारे पास पहले ही चरण में 38 हजार एकड़ लैंडबैंक मौजूद है। 46 साल में पहली बार हमारी सरकार में ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार है, वहीं झांसी में हम पहले ही चरण में एयरपोर्ट देने जा रहे हैं।

संपूर्ण भारत में शराबबंदी की मांग को लेकर 30 जनवरी को जंतर मंतर पर सत्याग्रह

लखनऊ। राष्ट्रीय शराब बंदी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आगामी 30 जनवरी 2024 हमारे प्यारे बापू के बलिदान दिवस पर दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले शराब बंदी सत्याग्रह की पूर्व तैयारी में लखनऊ स्थित मोर्चा कार्यालय 114, इन्साफ नगर पर मुर्तजा अली की देख रेख में आर्य समाज के प्रधान देवेंद्र पल जी की अध्यक्षयता में बैठक हुई । बैठक में सर्व सम्मत निर्णय लिया गया की 1000 सत्याग्रही की भागीदारी और उनके दिल्ली पहुंचने की जिम्मेदारी सभी साथियों ने ली है बैठक में यूथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष्य राजकुमार जी ने सत्याग्रह

में 200 सत्याग्रही पहुंचाने का एलान किया ! आर्य समाज के प्रमुख देवेंद्र पाल वर्मा जी ने बड़ी संख्या में आर्य समाजियों को दिल्ली अपील की है ! शराबबंदी संघर्ष समिति के महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हलीमा अजीम और इशरत बाग साहब ने मीडिया की जिम्मेदारी ली है.! राष्ट्रीय शराबबंदी संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति के लिए सदस्यों का ऐलान हुआ है जिसमें मुख्य रूप से आर्य समाज प्रमुख देवेंद्र पाल वर्मा सुल्तान सिंह, पी०सी कुरील, आरबी लाल, मुर्तुजा अली, शराबबंदी संघर्ष समिति के राष्ट्रीय महासचिव मिर्जा इशरत बाग, हलीमा अजीम, संजीव श्रीवास्तव उन्नाव, गिरजेश पांडे उन्नाव, राजेश कुमार सिंह, शाहिद सिद्दीकी खुर्शीद सिद्दीकी फहद हसन यह सब उपस्थित रहे मीटिंग में।

काकोरी जैन मंदिर के मांगलिक भवन का भव्य शिलान्यास समारोह सम्पन्न

लखनऊ। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट व सकल दिगम्बर जैन समाज की ओर से श्री पार्श्वनाथ धाम मन्दिर काकोरी में क्षमामूर्ति आचार्य 108 विशद सागर महाराज के सानिध्य में मांगलिक भवन का भव्य शिलान्यास समारोह गुरुवार को सम्पन्न हुआ। संयोजक विशाल जैन ने बताया कि मन्दिर में प्रातः 8 बजे याग मंडल विधान शुरू हुआ। 11 बजे शोभा यात्रा उसके बाद 12 बजे शिलान्यास हुआ। मांगलिक भवन का शिलान्यास श्रीमती साधना जैन, श्रेणिक जैन, निहारिका जैन ने किया। इसी क्रम में गोमतीनगर निवासी स्व. सुधीर कुमार जैन की स्मृति में निर्मित आहार कक्ष का लोकार्पण हुआ। शांतिधारा हेमंत जैन दिल्ली स्वदेश जैन दिल्ली, शास्त्र भेंट मोनू जैन गोमती नगर, अभिषे जैन, नितिन जैन, उदय कागजी याहिया गंज, महाराज जी को अर्घ्य समर्पण जैन समाज शाहबाद मोहम्मदपुर दिल्ली, विशेष शांतिधारा धर्मवीर जैन, आशु जैन अनिल जैन, संजय जैन इंदिरानगर। दोपहर का शास्त्र भेट डा अतुल

जैन इन्दिरानगर, संदीप जैन गोमती नगर, पाद प्रक्षालन डॉ नीरज जैन, धर्मवीर जैन इंदिरा नगर एवं संदीप जैन गोमती नगर ने किया। पूजन कार्य पंडित विकर्ष शास्त्री व आशीष जैन के संगीत निर्देशन में पूजन किया। प्रवचन में आचार्य श्री विशद सागर महाराज ने कहा कि संसार में वही जीव वंदनीय, पूजनीय हैं, जिन्होंने देह से ममत्व छोड़ दिया। घर, देश और संसार से मोह छोड़ना सरल है। जगत का राग छोड़ना सरल है, लेकिन देह का राग छोड़ना बहुत कठिन है। देह के ममत्व में जीव डूबा रहता है। इसे सजाने संवारने में व्यस्त रहता है। बालक से किशोर, युवा, अधेड़ और बुजुर्ग होने तक देह के महत्व में डूबा रहता है।

अवध की आवाज हिन्दी दैनिक, प्रकाशक ,मुद्रक व स्वामी,अनिल कुमार सिंह द्वारा स्काई लाइन प्रिन्टर्स,119/23 खन्दारी लेन, लालबाग, लखनऊ उ0प्र0 से मुद्रित तथा डी–97/3 व 7,सेक्टर–7, इन्दिरा नगर,लखनऊ,उ0प्र0 से प्रकाशित। सम्पादक अनिल कुमार सिंह फोन : 0522–4340954 मो0–7905407289, Email: avadhkiaawaz@gmail.com

R.N.I.- UPHIN/2012/45127

नोट : समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादोंका न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।